राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 288

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

प्रगति

समाचार पत्र

मई 2019

डब्ल्यु आई एस ई - एसएचजी उद्यम में महिलाओं की सहभागिता

3 डब्ल्यु आई एस ई - एसएचजी उद्यम में महिलाओं की भागीदारी

विषय-वस्तु

6
एनआईआरडीपीआर परिसर में वनस्पति और जीव अध्ययन

8
मत्स्य पालन क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और सतत आजीविका को बढ़ावा देने में एस एंड टी संस्थानों की भूमिका पर कार्यशाला

10
एमवाईआरएडीए - गुलबर्गा के लिए क्षेत्र दौरा

12
एनआईआरडीपीआर महा परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए कार्यशाला

13
एनआईआरडीपीआर में उत्तराखंड राज्य से निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन दौरा

15
सामुदायिक रेडियो केंद्र, पस्तापुर गांव का क्षेत्र दौरा

17
सात देशों के प्रतिनिधियों द्वारा एनआईआरडीपीआर का दौरा

18
डीडीयू-जीकेवाई के तहत ग्रामीण युवाओं के प्रतिधारण के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला

19
पशुधन के माध्यम से बेहतर आजीविका पर लाइब्रेरी टॉक

20
पशुधन के माध्यम से बेहतर आजीविका को बढ़ावा देने पर टीओटी कार्यक्रम

21
मॉडल सतत खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण

23
ग्रामीण उद्यमिता, नवाचार और वित्तीय समावेशन पर टीओटी कार्यक्रम

ढोकरा कला पर कर्य करती हुई घरवा महिला

डब्ल्यु आई एस ई - एसएचजी उद्यम में महिलाओं की सहभागिता

भारतीय संविधान की केन्द्रीय स्थिति और अवसर की समानता को बढ़ावा देना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाले सहभागी लोकतंत्र में निहित है। भारत में स्व-सहायता समूह और पंचायती राज प्रणाली दोनों समावेशी और लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण संस्थान हैं।

एसएचजी ने महिलाओं को स्वायत्तता एवं आत्मविश्वास, का बड़ा अहसास दिलाया है, और सामाजिक संबंधों और ग्रामीण गतिशीलता को बदल रहा हैं। आज, एसएचजी ऋण के लिए केवल एक माध्यम से कई अधिक हैं - वे 'परिवर्तन एजेंट हैं', महिलाओं को समान अवसर प्रदान करते और उन्हें सशक्त बनाते हैं। हालाँकि, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए एसएचजी को तंत्र में परिवर्तित करना समय की मांग है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि के बाद सूक्ष्म और लघु उद्यम दूसरे सबसे बड़े रोजगार उत्पादक हैं, लेकिन उनके उत्तरजीविता के लिए आवश्यक सहायता प्रणाली सीमित हैं। विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए उनके आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण, वित्त और बाजार तक पहुंच सीमित है। इसलिए, सतत आर्थिक विकास के एजेंट बनने में बहुत कम एसएचजी सफल रहे हैं।

> **“ हमारे गाँव की लाखों महिलाएँ जानती हैं कि बेरोजगारी क्या है। उन्हें आर्थिक गतिविधियों की पहुँच प्रदान करें और वे सत्ता और आत्म विश्वास तक पहुँच प्राप्त करेगी जिसके लिए वे अब तक अजनबी रही है ”**
>
> **महात्मा गांधी**

जीने क लिए कम और बहुत अल्प संसाधनों के साथ, अधिकांश एसएचजी अल्पविकसित रह गए हैं, और उत्पादन, मूल्य संवर्धन, बाजारों तक पहुंच आदि के मामले में विकास उनके लिए एक बड़ी चुनौती रही है।

थोडी सी बचत और बैंक-ऋण संयोजन द्वारा गरीबी से बाहर निकलने का कठोर कार्य स्वयं सहायता समूहों के गठन द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब यह कामयाब महत्वूपर्ण है कि निरंतर और समृद्ध होने के लिए एसएचजी को अपने 'कम्फर्ट जोन' से बाहर आना होगा, मौजूदा बाजार ताकतों से मुकाबला करने और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनने के लिए खुद को तैयार करना होगा।

ग्रामीण लोगों की क्षमता का निर्माण करने के अपने प्रयास में; समुदाय संग्रहण पर ध्यान देने, संबंध स्थापित करने और प्रक्रिया को अधिक सहभागी और सार्थक बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने एसएचजी में व्यापार कौशल को विकसित करने और उनके मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक उल्लेखनीय कदम उठाया है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के महत्व को समझने पर भी ध्यान दिया गया है।

इस पहल के भाग के रूप में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के संकाय सदस्यों ने उन स्वयं सहायता समूहों की शिनाख्त करने के लिए पांच उत्तर-पूर्वी राज्यों

कढ़ाई के काम में लगे एसएचजी सदस्य

सहित 17 राज्यों का दौरा किया जिनके साथ छात्र प्रभावी ढंग से काम कर सके और उन्हें जीपीडीपी में सहायक बनने में प्रशिक्षित कर सकते हैं।

उन एसएचजी की पहचान करने पर जोर था जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते थे:

- गैर-एसवीईपी ब्लॉकों से अधिमानतः एक राज्य में तीन से पांच एसएचजी
- बाजार तक पहुंच के बिना दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है
- हस्तशिल्प, हथकरघा या विदेशी, राज्य-विशिष्ट उत्पाद का उत्पादन करने वाले एसएचजी

एनआईआरडीपीआर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे छात्रों ने उनके 35 दिनों के संगठनात्मक इंटर्नशिप के भाग के रूप में, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल का दौरा किया।

'वास्तव में क्या हो रहा है' की वास्तविक जाँच करने वाले इन छात्रों ने इन राज्यों में एसएचजी महिलाओं की जरूरतों को समझने की कोशिश की और एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के डिजाइन और विपणन को सुधारने के संबंध में समर्थन दिया।

इंटर्नशिप से छात्रों को ग्राम सभा के कामकाज और परियोजना निर्माण में जीपीडीपी की भूमिका के बारे में बेहतर रूप से समझने में मदद मिली है।

छात्रों को 2 सदस्यों के समूह में बाँटा गया, जिसमें एक छात्र 1-वर्षीय पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम से और दूसरा 2-वर्षीय पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रम से था। मिश्रित समूह निर्माण करने का उद्देश्य 1 वर्षीय कार्यक्रम के छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करने बाद 2-वर्षीय पीजी छात्रों द्वारा स्वयं सहायता समूह को निरंतर सहायता प्रदान करना है।

एसएचजी की गतिशीलता को समझने में छात्रों को सक्षम बनाने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक समूह को एनआईआरडीपीआर के एक संकाय सदस्य को सौंपा गया था।

एसएचजी महिलाओं के साथ गांवों में रहने से छात्रों को ग्रामीण स्थितियों से परिचित होने में मदद मिली और ग्रामीण लोगों की चुनौतियों और जमीनी वास्तविकताओं से परिचित हुए। यह संकाय और छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ सीखने की एक महान पहल है।

छात्रों ने आय गतिशीलता की तुलना में व्यय व्यवहार को समझने के लिए प्रत्येक एसएचजी सदस्यों के परिवार का आधारभूत सर्वेक्षण किया और स्वयं सहायता समूह की सूक्ष्म निवेश / ऋण योजना का भी विश्लेषण किया। छात्रों ने एसएचजी द्वारा उधार लेने के कारणों के साथ-साथ उधार लेने के विभिन्न स्रोतों की भी जानकारी एकत्र की। इस अभ्यास से उन्हें यह पहचानने में मदद मिली कि एसएचजी को संस्थागत स्तर के किस स्तर पर रखा गया है और उन्हें मजबूत करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से कैसे हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

पंपोर (जम्मू और कश्मीर) के केसर से लेकर एजवाल (मिजोरम) के केले वेफर्स तक कश्मीरी शॉलों से लेकर मणिपुरी फानेक तक, सिक्किम में अचार बनाने से लेकर पंजाब के सूखे अदरक के आइटम तक, गुजरात और राजस्थान के बांदिनी कपड़े से लेकर पश्चिम बंगाल की कांथा साडी की सिलाई तक, पंजाब के फुलकारी दुपट्टे से लेकर त्रिपुरा की रिग्नाई और रिसा तक, बस्तर (झारखंड) की बेल मेटल वर्क से लेकर बिहार के मधुबनी पेंटिंग तक; छात्रों ने स्थिति, पैकेजिंग और उनके उत्पादों की बेहतर दृश्यता के लिए रणनीति बनाने में एसएचजी की मदद की।

विभिन्न संस्थानों में अभिसरण के बिना कोई विकास समग्र नहीं होता। इसलिए, छात्रों ने अन्य ग्राम स्तरीय संस्थानों जैसे आंगनवाड़ियों, पीएचसी, स्कूलों और ग्राम पंचायत के साथ एसएचजी के अंतर-संबंधों को समझने का प्रयास किया।

छात्रों ने ग्राम सभा में विभिन्न योजनाओं से धन प्रवाह की संरचना के बारे में भी जाना, अंतराल की पहचान की और उन्हें कम करने के तरीके सुझाए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत, ग्राम और जिला पंचायतों को समग्र परियोजनाओं को विकसित करने का काम सौंपा गया जो स्थानीय विकास आवश्यकताओं के आधार पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

चूंकि यह पहली बार है कि ग्राम पंचायतें परियोजना प्रस्तावों की अवधारणा पर आधारित हैं, ऐसे परियोजना प्रस्तावों के निर्माण में उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है।

कौना हस्तकला

पंजाबी दरी

कश्मीर से पश्मीना शाल का काम

एसएचजी सदस्यों द्वारा हस्तनिर्मित कंबल

हिमाचल प्रदेश से पाइन सुई काम

संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में, छात्रों ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में एसएचजी को सक्षम सुविधाकर्ता बनने में एक प्रभावी भूमिका निभाई। छात्रों ने उनके उत्पादों के विपणन में एसएचजी की मदद करने के लिए रचनात्मक तरीके भी तैयार किए, एसएचजी के विभिन्न उत्पादों के लिए व्यवसाय विकास योजना बनाई और एसएचजी के उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करने के लिए रचनात्मक तरीके भी तैयार किए। इन एसएचजी को एनआईआरडीपीआर में वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले 'आरटीपी मेले' में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।

एसएचजी महिलाओं के साथ छात्रों की बातचीत और गरीबी से बाहर आने के लिए इन महिलाओं की कठिन यात्रा ने इस दृढ़ विश्वास को मजबूत किया है कि गरीबों का संगठन उनके सशक्तीकरण के लिए एक आवश्यक उपकरण है।

इंटर्नशिप एनआईआरडीपीआर का एक और कदम है, अपने छात्रों के माध्यम से, ग्रामीण महिलाओं की कठिनाइयों को समझना, उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों में सक्रिय रूप से शामिल करना और सरकार को नीतियों का मसौदा तैयार करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता करना है।

एसएचजी, अर्थव्यवस्था के नए इंजन हैं, लेकिन मुख्य बाधाएं जैसे वित्त, आपूर्तिकर्ताओं से ऋण की सीमा गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन करने के लिए नई तकनीक, मूल्यवर्धन, समय पर वितरण और विपणन आवश्यकता को पूरा करना है। अब एसएचजी के पास दीर्घकालिक दृष्टि होने और अल्पावधि में अस्तित्व पर ध्यान न देने का समय आ गया है।

स्वयं सहायता समूह को उद्यम और उद्यमिता की नई चुनौतियों की ओर बढना है। महिला विकास के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। एसएचजी उद्यम, अनिश्चित रूप से, बेहतर विकास मार्ग प्रदान करेंगे और महिलाओं को स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करके उत्पादक उद्यम से जुडने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

जीपीडीपी में सुधार के लिए ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए मजबूत एसएचजी नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। एसएचजी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और पीआरआई के साथ उनके अभिसरण से निश्चित रूप से बेहतर सामुदायिक भागीदारी में मदद मिलेगी। सहक्रियाओं का निर्माण और एसएचजी-पीआरआई के बीच जैविक संबंध विकसित करना, आजीविका अवसरों को बढ़ाने और गाँव के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एक मजबूत एसएचजी नेटवर्क निश्चित रूप से 'निरंतर' और 'साझात्मक' आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। अब समय प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से विकास और विस्तार के लिए शासन की विभिन्न लोकतांत्रिक इकाइयों के मध्य सहयोग का है।

नोट: 1. अपने स्थापना दिवस समारोह के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर 2003 से 'ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला' का आयोजन कर रहा है। मेला, जो कि एक वार्षिक कार्यक्रम है, ग्रामीण कारीगरों और एसएचजी के लिए अपने अद्वितीय हस्तशिल्प, हथकरघा, जनजातीय आभूषण, ग्रामीण शिल्प, खिलौने, वुड वर्क, पारंपरिक खाद्य पदार्थ आदि को प्रदर्शित करने का एक अनूठा मंच है।

सुश्री हेमांगी शर्मा
विशेष कार्य अधिकारी
उप महानिदेशक
डॉ. आकांक्षा शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीडीसी)
कवरपेज डिजाइन: **श्री वी. जी. भट**

एनआईआरडीपीआर परिसर में वनस्पति और जीव अध्ययन

रॉकी आउटक्रॉप्स – व्यूपॉइंट से अवलोकन

एनआईआरडी परिसर में आर्द्रभूमि / नदी तट पर्यावास

एनआईआरडी परिसर में घनी झाड़ी वनस्पति, चट्टानी बहिर्वाह

घनी झाड़ी वनस्पति : व्यू पॉइंट से देखें

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद (17°18'47.73"एन, 78°24'5.45"ई) में स्थित है, जो लगभग 176 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जीवित संसाधन (पौधे, जानवर और रोगाणु) और उनके निवास स्थान जैव विविधता का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। उनके बीच आपसी बातचीत मानव समाज को मूर्त और अमूर्त लाभ् प्रदान करती है। इस संदर्भ में, परिसर के विभिन्न प्रकार के आवास में वनस्पतियों और जीवों के वितरण पैटर्न को समझने का प्रयास किया गया था। एनआईआरडीपीआर की जैव विविधता पर वर्ष 2017 और 2018 में आधारभूत (बेसलाइन) अध्ययन किए गए। एआईएनपी वीपीएम के शोधकर्ताओं ने मासिक आधार (हर महीने 10 दिन) पर एनआईआरडीपीआर परिसर का दौरा किया और जैव विविधता को रिकार्ड किया।

क्षेत्र

- विभिन्न निवास स्थितियों में विभिन्न अंतरालों पर जीवों और वनस्पतियों का आकलन
- कीस्टोन प्रजातियों और आरईईटी प्रजातियों की पहचान, और विलुप्त प्रजातियों की पुर्नजीविता के संकेत देना
- क्षेत्र-विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करना

जलवायु: अध्ययन क्षेत्र की जलवायु आम तौर पर 140 से 450 से तक के तापमान के साथ शुष्क होती है और क्षेत्र में सामान्य वर्षा 786.8 मिमी होती है, जो मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून से होती है। मिट्टी के प्रकार मुख्य रूप से काला कपास, लाल और भूरी रेतीली चिकनी बलुई होती हैं। अध्ययन क्षेत्र में ग्रेनाइट के विशिष्ट चट्टानी बहिर्वाह सामान्य हैं।

वनस्पति: परिसर के अविभाजित क्षेत्र में वनस्पति घने झाडी के जंगल से लेकर मध्यम झाडी के मध्य होती है। मूल्यांकन अवधि के दौरान, 121 पीढी और 62 परिवार के कुल 176 प्रजातियाँ जिनमें 52 प्रजातियों के पेड, 32 झाडियों की प्रजातियाँ, 65 जड़ी-बूटियाँ और 28 बेल पाए गए। वन निवास में प्रमुख पेड़ों में अल्बिजिया अमारा, कैसिया फिस्टुला, बबूल चुंद्रा और बबूल हारिडा शामिल हैं। पाए जाने वाले छोटे पेड़ों से लेकर बड़े झाड़ियाँ में ग्रिवा आर्बिकुलेटा, यूफोरबिया एंटिकोरम, हेलिक्टेरेस इसोरा, फ्लुएगिया ल्यूकोपिरस, डिक्रोस्टैचिस सिनेरिया और ज़िज़िफह जुजुबा शामिल हैं। अधिकांश वनस्पति पौधे वार्षिक हैं, जो मानसून की अवधि के दौरान विशिष्ट मौसमी पौधो का प्रदर्शन करते हैं। पाए गए महत्वपूर्ण प्रजातियों के संघ है, क्लियोम-हेलियोट्रोपियम, क्लेओम हेलियोट्रोपियम-टेफ्रोसिया और टेफ्रोसिया-हेलियोट्रोपियम मानसून के बाद की अवधि में, वाल्थरिया इंडिका जमीन पर अधिक बढ जाते है। अन्य उगने पौधे हैं इंडिगोफेरा कार्डिफोलिया, क्रोटलेरिया रामोसिसिमा, कार्चोरस ट्राइलोक्युलैरिस, जस्टीशिया वाहली, जस्टीशिया ग्लौका, डिट्रेकैन्थस प्रोस्ट्रेटस, सिट्रुलस कोलोसिन्थिस, पॉलीकार्पिया कोरिम्बोसा और ब्लेफेरिस मेडिरासपेटेंसिस, इसके साथ घास की प्रजातियाँ जैसे हेटरोपोगोन कान्टोरस एवं सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस है और बेलों में अब्रस प्रिकटोरियस, एब्रसप्रिकटोरियस, कार्डियोस्पेरमम हेलिकाकाबम, सिस्सस क्वाडैंगुलरीज, मुकिया मेडिरासपेटाना, इपोमिया आस्कुरा, रिविया हाइपोक्रेटेरीफार्मिस और मेरिमिया एजिप्टिया आदि है।

आईयूसीएन रेड-सूचीबद्ध प्रजातियाँ जैसे संतलम एल्बम (चंदन), क्लोरोजाइलॉन स्वेटेनिया (पूर्व भारतीय सैटिनवुड) और डालबर्गिया लैटिफोलिया (भारतीय शीशम), जिन्हें 'दुलर्भ' श्रेणी में 'विलुप्त' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है - संभावित औषधीय महत्व की अन्य प्रजातियों में शामिल हैं। स्ट्रिकनॉस नक्स-वोमिका (पायजन नट), केसिया फिस्टुला (गोल्डन शवर) और स्टेरकुलियारन्स (गम कराया) फल देने वाले पेड़ों में एनाना स्क्वैमोसा (कस्टर्ड-सेब) शामिल हैं जो चट्टानी फसलों के साथ बहुतायत से वितरित होते हैं।

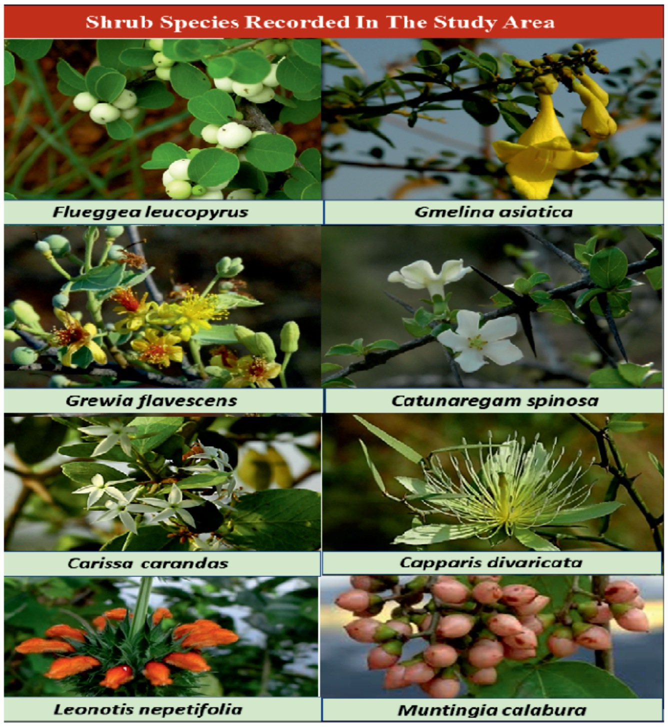

मॉनसून मौसम के दौरान, शाकाहारी वनस्पति शानदार विकास के साथ फलती-फूलती है जो एक सीमित स्थान में 64 से अधिक प्रजातियों के साथ विख्यात है। मौसमी भिन्नता क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य घटना है जो मानसून, पोस्ट-मानसून और प्री-मानसून के बीच भारी उतार-चढ़ाव दिखाती है।

जीवजंतु: अध्ययन की अवधि के दौरान, 5 वर्ग और 8 परिवारों से संबंधित कुल 12 स्तनधारी प्रजातियां, 21 वर्ग और 49 परिवारों से संबंधित 121 एवियन प्रजातियां, 52 सरीसृप प्रजातियां 4 परिवारों से संबंधित 14 उभयचर और 13 परिवारों से 38 सरीसृप संबंधित 38 सरीसृप हैं) , 39 तितली प्रजातियाँ और 100 से अधिक कीड़ों की प्रजातियों को प्रलेखित किया गया। पक्षी प्रजातियों में, 3 प्रजातियाँ थीं – पेंइटेड स्टार्क (माइक्टेरिया ल्यूकोसेफला), ब्लैक हेडेड इबिस (थ्रेसकिओर्निस मेलानोसेफालस) और ओरिएंटल डार्टर (अनहिंगा लनोगास्टर) - जिन्हें आईयूसीएन की 'विलुप्त के समीप' श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तेलंगाना क्षेत्र में पहली बार शीतकालीन प्रवासी ब्लू कैप्ड रॉक थ्रश (मोंटीकोला सिनेक्लोरिन्चस) को रिकॉर्ड किया गया और उसकी तस्वीरें खींची गईं। हेरपेटोफौना, जो कि कैसिबियन की एक प्रजाती है, पहली बार तेलंगाना में रिकार्ड की गई थी, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में कैसिलियन की कोई पिछली रिपोर्ट नहीं थी। स्तनधारियों में, जंगली सूअर (सुस स्क्रोफा) सबसे प्रमुख है, जिससे विभिन्न आवासों को भारी नुकसान होता है। अवधि के दौरान सृजित आधारभूत डेटा क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों के बारे में विचार प्रदान करते हैं और भविष्य के प्रयासों के लिए उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए आवाज देते हैं।

डॉ. रवींद्र एस गवली
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएनआरएम
सौजन्य: एआईएनपी वीपीएम

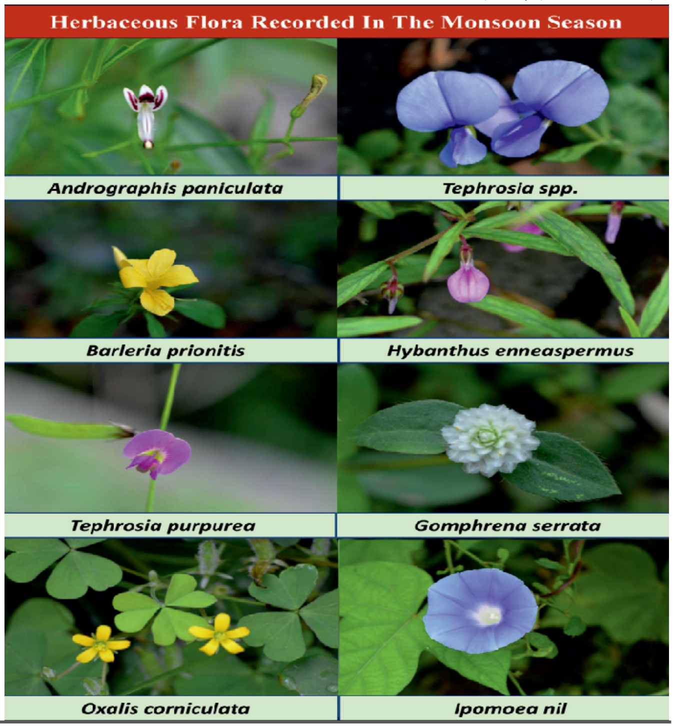

मत्स्य पालन क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और सतत आजीविका को बढ़ावा देने में एस एंड टी संस्थानों की भूमिका पर कार्यशाला

अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रो. आई. ब्राइट सिंह

राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सहयोग से 14 मई, 2019 को नवोन्मेषी एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी आई ए टी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडपीआर), ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और सतत आजीविका को बढ़ावा देने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों की भूमिका पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, सीआईएटी के स्वागत भाषण से कार्यशाला प्रारंभ हुई। अपने संबोधन में, उन्होंने कार्यक्रम के विवरण और कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य को उल्लेखित किया - विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, कार्यान्वयक एजेंसियां और वित्तीय संस्थान जैसे विभिन्न हितधारकों को एक जुट करना ताकि वे समग्र तरीके में पूर्ण स्थिति / दायरे को समझ सकें और भारत सरकार द्वारा प्रारंभ 'नील क्रांति योजना' के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके दृष्टिकोण से संयुक्त रूप से योगदान देते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में योगदान कर सकें।

कार्यशाला में मत्स्य पालन क्षेत्र पर काम करने वाले विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रतिनिधि, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप जैसे विभिन्न राज्यों के मत्स्य पालन विभाग से प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थान और मत्स्य पालन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

परिचर्चा की शुरुआत करते हुए, डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने प्रौद्योगिकी अंतरण, जिसे प्रौद्योगिकी भागीदारों के माध्यम से प्रदर्शित और विकसित किया गया है द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए एनआईआरडीपीआर के माध्यम से विभिन्न पहल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का धन्यवाद करने के अलावा सीईओ, एनएफडीपी, आयुक्त, मत्स्य पालन विभाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एनएफडीपी, आयुक्त, मत्स्य पालन विभाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी ने इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक तटीय किसान को अर्थव्यवस्था में योगदान देने के अलावा अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए आय के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में मत्स्य पालन को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा जो शहरों में रह कर सफेद कॉलर की नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे उसी समय प्रशिक्षण प्राप्त करके पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में मत्स्य पालन कर सकते हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि नाबार्ड और वाणिज्यिक / क्षेत्रीय बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों को नवीनतम तकनीकों को अपनाकर मत्स्य पालन को प्रारंभ करने में युवाओं और मछुआरों के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आगे आना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनएफडीबी, जो मत्स्यिकी क्षेत्र के प्रचार में महान कार्य कर रहा है, हमेशा नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए इस क्षेत्र में इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार रहेगा।

डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी ने महसूस किया कि प्रौद्योगिकी का प्रसार समय की मांग है जिस पर भारत सरकार की 'नीली क्रांति' योजना जोर डाल रही है। आगे उन्होंने देश भर के विभिन्न संस्थानों को सफल मॉडलों के साथ आने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उन्हें साझा और कार्यान्वित किया जा सके, क्योंकि गरीबी को कम करने या मिटाने का रहस्य नई तकनीकों को सीखने और अपनाने में निहित है।

डॉ. सी. सुवर्णा, आई एफ एस, आयुक्त, मात्स्यिकी विभाग, तेलंगाना सरकार ने पायलट परियोजना के रूप में केज कल्चर के लिए पिंजरों में बीज पालन और प्रजातियों के विविधीकरण पर संक्षिप्त प्रस्तुति प्रदान की। उन्होंने कहा कि 700 पिंजरों के साथ उन्होंने प्रयोग किया और 'मुरल' नामक मछली के बीज पालन की कोशिश की, जिसमें पहली फसल ही विफल हो गई। दूसरे प्रयोग के साथ, वे केवल थोड़ी मात्रा में मछली का पालन कर सके। उन्होंने कहा कि केज कल्चर इकाइयों का मूल्यांकन बीज की गुणवत्ता, हवा के वेग, फ़ीड की गुणवत्ता आदि पर निर्भर करता है। वह चाहती थीं कि अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और मत्स्य विशेषज्ञ अपने तकनीकी ज्ञान के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र में सक्रिय सहयोग देने के लिए आगे आए और कहा कि क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में प्रदान किए जा रहे समर्थन और तेलंगाना में विभिन्न जिलों के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकियों और उपकरणों की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए आरटीपी, एनआईआरडीपीआर धन्यवाद दिया।

एनएफडीबी के वरिष्ठ कार्यकारी (तकनीक) डॉ. मन्ने पर्सिस ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन प्राथमिक स्तरों पर 14.5 मिलियन से अधिक लोगों और मूल्य श्रृंखला के साथ और अधिक के लिए विभिन्न संसाधनों एवं संभावित जुडाव के साथ एक उभरता हुआ क्षेत्र है । आगे उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में लगभग 0.91 प्रतिशत और कृषि जीडीपी (2014-15) में 5.23 प्रतिशत का योगदान प्राप्त हुआ है । भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश बन गया है, जो वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग 6.3 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 5 प्रतिशत उत्पादन करता है ।

डॉ. मन्ने पर्सिस ने आगे कहा कि भारत सरकार ने देश की मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के एकीकृत विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की दृष्टि से 'नीली क्रांति' (नील क्रांति मिशन) नामक योजना शुरू की है, जो स्थिरता, जैव सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मछुआरों और मछली किसानों की आय की स्थिति में पर्याप्त सुधार करता है ।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री विजय कुमार ने कहा कि वह मत्स्य क्षेत्र की क्षमता को समझ सकते हैं और मछुआरों को धन मुहैया कराने के इच्छुक हैं । उनके अनुसार, सामूहिक रूप से काम करना समय की जरूरत है । "मछुआरों को एक साथ आना चाहिए और इंटरनेट मार्केटिंग शुरू करके 'मछुआरे फोरम' का निर्माण करना चाहिए । उन्होंने कहा कि मत्स्य उत्पादों के संरक्षण, भंडारण और पैकेजिंग में सुधार करने और निरंतर विपणन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता का पता लगाना चाहिए ।

श्री विजय कुमार ने कहा कि नाबार्ड के पास मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए रू. 120 करोड़ का विशिष्ट निधि है और कहा कि कार्यशील पूंजी के लिए सस्ती दरों पर अल्पकालिक ऋण, इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध हैं । अंतिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि मछुआरे पीड़ित न हों। बिचौलियों को हटा दिया जाना चाहिए और मछुआरों को अधिकतम लाभ अर्जित करना चाहिए ताकि यह क्षेत्र पनप सके ।

प्रो. आई. एस. उज्ज्वल सिंह, नेशनल सेंटर फ़ॉर एक्वाटिक एनिमल हेल्थ ने 'बैकयार्ड रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर यूनिट' का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे एनएफडीबी के समर्थन और सहायता से ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर में स्थापित किया गया था । उन्होंने कहा कि 5.6 लाख रुपये के एक छोटे से निवेश के साथ लगभग तीन महीने के समय में कोई भी निवेश के तीन गुना राशि प्राप्त कर सकते हैं । मछली के अलावा, इकाई उच्च गुणवत्ता वाली खाद उत्पन्न कर सकती है, जिसका उपयोग फलों और सब्जियों के बागानों के लिए किया जा सकता है ।

कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अन्य विज्ञान और तकनीकी संस्थानों ने भी अपने विचार साझा किए और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एनआईआरडीपीपआर, एनएफडीबी की मदद ली।

इस पृष्ठभूमि के विरूद्ध एनआईआरडीपीआर मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि निर्जलीकरण तकनोलॉजी, बर्फ बनाने की मशीन, डिबोनिंग मशीन, स्टोरेज सुविधाएं, सोलर मिल, इको-हैचरीज के अलावा एनएफडीबी, राज्य मात्स्यिकी विभाग, आदि के साथ सहयोग में मछुआरों को प्रशिक्षित प्रदान कर रहा है ।

एनआईआरडीपीआर की राय है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी क्षमता की तुलना में अब तक जो कुछ किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है और इसलिए चुनौतियों की पहचान करने के लिए मत्स्य पालन पर काम कर रहे प्रौद्योगिकीविदों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है और उसी को दूर करने के लिए उपाय, और उपयुक्त विभागों एवं एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक समुदायों के साथ सहयोग में भविष्य के रोड मैप को विकसित करने के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप तैयार कर रहा है ।

कार्यशाला के दौरान, ग्रामीण प्रौद्योगिकी एनआईआरडीपीआर में स्थापित बैकयार्ड री-सर्कुलेटरी एक्वा कल्चर (आरएसी) यूनिट का उद्घाटन प्रो. आई एस ब्राइट सिंह, डॉ. सी. सुवर्णा, आई एफ एस और डॉ. मन्ने पर्सिस के साथ डॉ. डब्ल्यु.आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति में किया गया ।

डॉ. रमेश सक्तिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर, सीआईएटी एवं पीडी, आरटीपी द्वारा धन्यवाद ज्ञापनके साथ कार्यशाला समाप्त हुई । प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए, डॉ. रमेश सक्तिवेल ने इच्छा जताई कि कार्यशाला के विचार-विमर्श से वांछित लाइनों पर मात्स्यिकी क्षेत्र के सुधार और उक्त क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण रोजगार, उद्यमिता के सृजन में अधिक समन्वित तरीके से काम करने में मदद मिलेगी।

प्रतिभागियों को आरएसी प्रौद्योगिकी का ब्रीफिंग

सौर फ्रीजिंग प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन-सह-परिचय

एमवाईआरएडीए -गुलबर्गा के लिए क्षेत्र दौरा

एमवाईआरएडीए के लिए क्षेत्र दौरे के दौरान डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई और छात्र

जैसा कि भारत में मई 2019 में भीषण गर्मी का अनुभव किया जाता है, यह किसी भी तरह से ध्यान देने योग्य बात है कि ग्रामीण परिदृश्य में अनुभव की गई गंभीरता महत्वपूर्ण है। शुष्क परिदृश्य में सांस लेने के लिए भूरी मिट्टी की छलकती हुई बेस्वाद वनस्पति दिखाई देती है । अधिक गंभीर वही अभिव्यक्ति थी जो निवासियों अर्थात मनुष्यों और जानवरों दोनों के बीच गर्मी से बचने के लिए खोखले और हताश नज़र देखने में आयी।

जमीनी स्तर पर मामलों की स्थिति का एक बेहतर दृष्टिकोण पाने की खोज से 12-13 मई, 2019 तक हमने गुलबर्गा में एमवाईआरएडीए (मैसूर पुनःस्थापना एवं विकास एजेंसी) के मुख्यालय पहुँचे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य गांव में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के कामकाज को समझना था।

एसएचजी आंदोलन को लोकप्रिय रूप से बैंक ऋण के रूप में जाना जाता है जब एसएचजी समूहों को दिया जाता है जिसमें 12-20 सदस्य होते हैं । एकमुश्त नकद पाने के लिए शहरी भारत के किटी पार्टियों में चिट उठाने जैसे रही, इन बैंक ऋणों को एसएचजी को दिए जाते हैं, जो इसे एक समय में एक / दो सदस्य को सौंपता है, और समूह का सामंजस्य सुनिश्चित करता है कि चुकौती में कोई चूका नहीं है । एसएचजी समूह हर हफ्ते सभी सदस्यों से एक मूल न्यूनतम राशि एकत्र करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे किटी पार्टियों में मासिक पैमाने पर किया जाता है। लेकिन किटी पार्टियों के विपरीत, जहां मनोरंजन के लिए की जाती हैं, एसएचजी कई परिवारों के लिए जीवन रेखा हैं, जो पिछले 25 वर्षों में अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं या इससे भी कम जबसे वे एस एच जी आंदोलन में शामिल हुए है, ग्रामीण भारत को चुपचाप बदल रहा है। वित्तीय मुद्दों, खातों के रखरखाव, पैसे के आंतरिक संचलन, ऋण की अदायगी आदि को संबोधित करने के लिए नियमित बैठकों के एक निश्चित प्रारूप पर एसएचजी कार्य करता है । एसएचजी लगभग हमेशा जेंडर-विशिष्ट होते हैं और महिलाओं द्वारा विशेष रूप से चलते हैं। ये महिलाएं उद्यमी होते हैं और ऋण चुकाने के लिए छोटे व्यवसाय चलाती हैं।

कमलापुर गाँव में जैसा कि ग्रामीण भारत के अधिकांश गाँवों में होता है, एक सहायता संगठन क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करता है। यहां पर सहायता संगठन है एमवाईआरएडीए (मैसूर पुनर्वास और विकास एजेंसी) जिसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका और क्षमता निर्माण से संबंधित कार्य दिया गया है। प्रत्येक गाँव को केंद्र सरकार और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा परिकल्पित ग्राम पंचायत विकास योजना को अपलोड करना होगा ताकि गाँव के नियोजन मूल्यांकन की योजना कार्यान्वित किए जाने वाले योजनाओं के प्राथमिकीकरण और सरकार से बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से धन आवंटन की सुविधा मिल सके। कई मामलों में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सभी महिला प्रतिनिधि, क्षेत्र में स्व-सहायता समूह के सदस्य भी होते हैं । ऐसा ही मामला कमलापुर का भी था जहां 18 पीआरआई सदस्यों में से लगभग 4 महिलाएँ गाँव के अलग-अलग एसएचजी से थीं। लेकिन, एसएचजी समूहों के साथ करीबी बातचीत में व्यक्त की गई वास्तविकताओं ने बहुत अलग दृश्य प्रस्तुत किया। जैसा कि आम तौर पर अविकसित राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार का मामला है, कर्नाटक गाँव के पास साझा करने के लिए अपना पिछड़ापन था।

यह बताया जाना चाहिए कि क्षेत्र में एमवाईआरएडीए द्वारा समर्थित 130 एचएचजी हैं । अध्ययन के नमूना क्षेत्र कमलापुर गाँव में लगभग 25 एचएचजी कार्यरत हैं । लगभग सभी एचएचजी सदस्य स्वतंत्र व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर हैं और भाग्यवती महिला सशक्ती समूह को छोड़कर पूरे एचएचजी द्वारा एक साथ कोई वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य उत्पाद का उत्पादन नहीं किया जा रहा है । एसएचजी केवल कुछ महीनों के लिए ही एक साथ काम करता है, फिर भी प्रति माह 50,000 रुपये का लाभ पैदा करता है । यह मौसमी है क्योंकि यह दालों की फसल के मौसम पर निर्भर करता है।

गुलबर्गा में एमवाईआरएडीए का नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी श्री एस.डी. कल्याणशेट्टी करते है। लेख में दिए गए सुझावों को उन्हें और क्षेत्र प्रबंधक श्री जितेंद्र बेलगुडी को दिए गए। एमवाईआरएडीए कम्युनिटी रिसोर्स यूनिट में आयोजित इस बैठक

श्रीमती ललिता, प्रबंधक और आठ अलग-अलग एसएचजी के सदस्य बातचीत के लिए उपस्थित थे। प्रत्येक समूह में 12-14 सदस्य हैं जो फलों की बिक्री, किराने की दुकान, चूड़ियों की बिक्री, फोटोकॉपी सेवा और लेमिनेशन, रोटी बनाना, अचार बनाना आदि जैसे व्यवसाय करते हैं। उन्होंने 1998 में एसएचजी में शामिल होकर अपनी सफलता की कहानियाँ साझा कीं, जब ये एसएचजी ज्यादातर स्थापित हो चुके थे। सीएमआरसी में नौ निर्वाचित सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष श्रीमती पार्वती कावेरी एसएचजी से आती हैं। इस बैठक के नतीजे के रूप में, निम्नलिखित कार्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है:

सबसे पहले, एसएचजी और पीआरआई के बीच एक विस्तृत कील होती है। एसएचजी सदस्य वित्तीय लेनदेन, वित्त आयोग अनुदान, केंद्र प्रायोजित अनुदान और पंचायत द्वारा प्राप्त अन्य अनुदानों पर लगातार जानकारी की मांग कर रहे हैं। ग्राम सभा बैठक के दौरान, एसएचजी महिलाओं को अपनी चिंता को खुलकर बताने की अनुमति नहीं दी जाती है।

दूसरा, एसएचजी सदस्यों ने पंचायत सदस्यों द्वारा मनरेगा के लाभार्थियों की पहचान में भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया। उन्होंने ऐसे मामलों की ओर ध्यान दिलाया, जहां कुछ सौ रुपये लाभार्थी को दिए गए थे और हजारों रूपए पंचायत सदस्य के खाते में भेजे गए थे, जिन्होंने योजना के तहत काम पाने के लिए प्रस्तुत सूची में लाभार्थी के प्रविष्टी की सुविधा दी थी।

तीसरा, एसएचजी सदस्यों को एक कदम आगे बढ़कर एक शिनाख्त उत्पादों की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया गया, जिनका विपणन कर और एसएचजी की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए अर्जित लाभों को जोड़ा जा सकता है।

चौथा, महिलाओं को एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रदान किए गए आरटीपी (ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क) प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वे यह पहचान सकें कि वे किस उत्पाद पर आराम से काम कर सकती हैं।

पांचवां, बिजली बिल को बचाने के लिए, एसएचजी के आदेश पर सोलार पैनल लगाए जा सकते हैं। गांव के विकास के लिए पीआरआई के साथ एक कार्यात्मक सहकारी संबंध में एसएचजी को लाने के लिए भारत सरकार के जोर पर उन्हें अपडेट किया गया।

एनआईआरडीपीआर की टीम एसएचजी के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए

छठी, महिलाओं को क्षेत्र में पानी की कमी की शिकायत थी। कमी के कारण, 25 प्रतिशत लोगों ने अपने शौचालयों का उपयोग नहीं किया और अभी भी खुले में शौच का अभ्यास जारी हैं।

सातवीं, गांव में पानी की कमी के कारण, मनरेगा कार्य के माध्यम से समुदाय भवन और पंचायत के स्वामित्व वाले अन्य भवनों के पास जल संचयन इकाईयों के निर्माण के लिए सुझाव दिया गया।

यह बताया गया कि एमवाईआरएडीए अकेले कर्नाटक राज्य में 50 सीएमआरसी की सुविधा देता है। इसलिए, यह सलाह दी गई कि सीएमआरसी के 50 प्रबंधकों को आरटीपी में बनाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों पर प्रशिक्षण दिलाने के लिए एनआईआरडीपीआर को प्रशिक्षण पर भेजा जाए। सीएनआरएम, एनआईआरडीपीआर के परामर्श से प्रशिक्षण कार्यक्रम में जल प्रबंधन को भी शामिल किया जा सकता है।

आरएसके (रितु संपर्क केंद्र) का दौरा

रितु संपर्क केंद्र कार्यालय का दौरा किया गया, और वहां के अधिकारी श्री प्रशांत के साथ हुई बातचीत से गाँव में हुए कुछ विकास वर्तमान में आरएसके कार्यालय 7-8 ग्राम पंचायतों के तहत 26 गांवों के साथ समन्वयन कर रहा है जो इस एसआरएस की निगरानी में आते हैं। कई वर्षों से कार्यात्मक होने के बावजूद इस केंद्र को हाल ही में एक नए स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। जलवायु, वाष्प घनत्व, हवा की गति, हवा की दिशा, हवा की तेजी आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए यह केन्द्र बुनियादी ढांचा संसाधन है। यह जानकारी केवल पंजीकृत किसानों को प्रदान की जाती है। प्रत्येक किसान को एक बार की पहचान संख्या दी जाती है और पंजीकरण प्रक्रिया में मदद की जाती है जो इस केंद्र में ऑनलाइन की जाती है। टीम ने दौरे से पहले पंचायत राज मंत्रालय के पोर्टल के तहत शिनाख्त अपलोड किए गए जीपीडीपी अंतराल को देखा था। शिनाख्त अंतरालों में मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी जांच क्लीनिक शामिल नहीं थे।

कार्यालय में दो कृषि अधिकारी और तीन कृषि विस्तार अधिकारी युक्त पांच कर्मचारी काम करते हैं।

आगे की प्रगति को सक्षम बनाने के लिए जमीनी स्तर पर अभिसरण के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव दिया गया:

यह देखा गया कि आरकेएस पहले से ही राज्य सरकार की योजनाओं के तहत जलागम प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह सुझाव दिया गया कि एमवाईआरएडीए को जलागम प्रबंधन में एसएचजी महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आरएसके कार्यालय के साथ सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

आरएसके अधिकारी श्री प्रशांत को सलाह दी गई कि वे अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेजों के साथ संबंध स्थापित करें। उन्हें आगे आरएसके के साथ पंजीकृत 26 गाँव के किसानों का एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की सलाह दी गई।

डॉ. आकाँक्षा शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई

एनआईआरडीपीआर महापरिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए कार्यशाला

महापरिषद के सदस्यों को संबोधित करते डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक

महा परिषद एनआईआरडीपीआर की पिछली बैठक के अनुवर्ती के रूप में, एनआईआरडीपीआर की महा परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए 28 और 29 मई, 2019 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई । इसका उद्देश्य जीसी सदस्यों को एनआईआरडीपीआर की सुविधाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और संस्थान के परिणामों में सुधार के लिए सदस्यों से सुझाव प्राप्त करना रहा । इसके अलावा, कार्यशाला का उद्देश्य एनआईआरडीपीआर के संकाय को महा परिषद के सदस्यों के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है ।

डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई । श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर भी उपस्थित थी। महानिदेशक ने महा परिषद के माननीय सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया और बताया कि कार्यशाला का आयोजन करने का उद्देश्य ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके अनुभवों के आधार पर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एनआईआरडीपीआर में महा परिषद के सदस्यों के साथ परिचयात्मक सत्र आयोजित करना, संस्थान के कार्यों और गतिविधियों को आगे बढ़ाना रहा है ताकि ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लिए इसे और अधिक सार्थक बनाया जा सके।
परिसर में इस कार्यशाला को आयोजित करने का अन्य कारण यह था कि ग्रामीण लोगों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही तकनीकी उन्नति के साथ जोड़ने में मदद करने के लिए कार्य अनुसंधान के रूप में एनआईआरडीपीआर के हस्तक्षेप की और सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना है, चाहे यह ऊर्जा हो, आवास, कृषि या उस मामले के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क के निर्माण के माध्यम से आजीविका और उद्यमशीलता गतिविधियों को उत्पन्न करने वाली आय। यह भी ध्यान में लाना था कि ऐसे हस्तक्षेप और गतिविधियाँ, जिनका ग्रामीण लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है, को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है ताकि संकट और ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए एमओआरडी के प्रमुख कार्यक्रमों को पत्र और भावना में लागू किया जा सके ।

"माननीय सदस्यों द्वारा संचालित संस्थानों के साथ आपसी सहयोग की संभावनाओं को भी प्रयासों के तालमेल के लिए पता लगाया जा सकता है," महानिदेशक ने इस बात पर जोर दिया ।

बाद में कुछ जीसी सदस्यों ने आरटीपी का भी दौरा किया और मछली पालन के लिए बैकयार्ड पुनरावृत्ति जलीय कृषि इकाई, मधुमक्खी पालन, लीफ प्लेट बनाने, उपयोग किए गए और रद्दी कागजों से कागज की तैयारी और इसके विभिन्न उत्पादों जैसे कैरी बैग, लिफाफे बनाना, फाईल कवर आदि और अन्य मितव्ययी नवाचार जैसे सीमेंट मोर्टार स्प्रेयर, पोल क्लाइम्बर, हैंड-हेल्ड सोलर लैंप आदि जैसे आय सृजन क्रियाकलापों पर पहल और प्रशिक्षण का सराहना किय । वे देश के विभिन्न हिस्सों से लाए स्थानीय सामग्री से बने आंतरिक सडकों और संरचना दोनों को देखकर खुश हुए, विशेषकर महानिदेशक का निवास जो कि आरटीपी में विकसित उपयुक्त आवास प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बनाया गया है ।

अगले दिन, जीसी सदस्यों ने तेलंगाना के महबूबनगर जिले के फारूकनगर ब्लॉक के हाजीपल्ले गांव का दौरा किया । इस गाँव को निर्मल ग्राम पुरस्कार (2008 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित) प्राप्त है और एक दशक से अधिक समय तक स्वच्छता के मामले में विशेष गाँव के रूप में खड़ा है, क्योंकि गाँव में प्रत्येक परिवार के लिए स्वयं का एक शौचालय है जिसका उपयोग 2007 से किया जा रहा है । संयोग से, यह गाँव 2008 से एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद का एक कार्य अनुसंधान गाँव रहा है । उन्होंने पंचायत की महिला सरपंच के साथ बातचीत की और उन्हें पंचायत के सचिव द्वारा पंचायत के सुचारू कामकाज के बारे में बताया गया और वह भी एक महिला ही थी । उन्होंने भूमिगत जल निकासी प्रणाली के साथ आंतरिक सीमेंट और स्वच्छ सड़कों की भी जाँच की। जीसी सदस्य उनके प्रयासों की अत्यधिक सराहना की ।

डॉ. राजेश के. सिन्हा, सहायक प्रोफेसर, सीआरटीसीएन और उनकी टीम द्वारा कार्यक्रम का संयोजन किया गया ।

एनआईआरडीपीआर में उत्तराखंड राज्य से निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन दौरा

उत्तराखंड के पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए पद्दतूपुरा ग्राम पंचायत के पदाधिकारी

पीआरआई में प्रशिक्षण निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमताओं को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । प्रशिक्षण उनके ज्ञान को बढ़ाता है और दैनिक आधार पर उनके कामकाज के दृष्टिकोण को बढ़ाता है, खासकर पंचायत की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को। विकास के परिप्रेक्ष्य में, विशेष रूप से पीआरआई क्षेत्र में, ग्राम पंचायत को चलाने में प्रभावी शासन के लिए प्रशिक्षण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की क्षमता को विकसित करना बहुत आवश्यक है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियाँ परिवर्तन के एजेंट हैं, इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को पीआरआई के बारे में पता होना चाहिए । चूंकि पीआरआई के लिए चुने गए चयनित प्रतिनिधि पहली बार चुने गए हैं, और गांव के कुलीन वर्ग के इशारे पर काम करते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से बाधाओं को सौंपने का प्रयास किया गया।

प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श पर प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद को प्रशिक्षण का कार्य सौंपा है । आवश्यकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए, डॉ. वाई. भास्कर राव, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के मार्गदर्शन में पंचायती राज के केंद्र पंचायत के दैनिक कामकाज में महत्वपूर्ण विषयों की एक श्रृंखला के साथ तीन दिनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन किया । प्रतिभागियों की जरूरतों के अनुसार कार्यक्रम में सत्रों और अवधि की योजना बनाई गई। 22 अप्रैल, 2019 से 16 मई, 2019 के दौरान कार्यक्रम को चरण-वार तरीके में आयोजित किया गया। संबंधित ब्लॉक के नोडल अधिकारियों सहित कुल 450 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 11 बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तराखंड के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिनमें से अधिकांश पहली बार प्रधान चुने गए थे। यह देखा गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुरुष और महिला दोनों निर्वाचित प्रतिनिधियों के लगभग समान अनुपात ने भाग लिया। सभी 11 बैचों में उपस्थिति से यह पता चलता है कि चयनित प्रतिनिधियों में से अधिकांश 40-50 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के थे। इसी तरह, प्रतिभागियों की शैक्षणिक योग्यताएँ मैट्रिकुलेशन से लेकर स्नातक स्तर तक अलग-अलग थीं। 11 बैचों की सामाजिक संरचनाएँ समान थीं।

कवर किए गए विषयों की श्रेणी

प्रशिक्षण कार्यक्रम में कवर किए गए विषय है - पंचायत शासन, नेतृत्व और प्रेरणा, ग्राम पंचायत विकास योजना और सतत विकास लक्ष्य, जेंडर – अनुकूल पंचायत, पंचायत में जेंडर और पोषण संबंधी मुद्दों को समझना, पंचायत के वित्तीय प्रबंधन, ग्राम पंचायत के लिए स्वयं के स्रोत राजस्व का सृजन आदि।

इन विषयों को पीआरआई में इसके महत्व के अनुसार युक्तिपूर्ण तरीके से निर्धारित किया गया था । आंतरिक सत्रों को संभालने के लिए, संबंधित अधिकार क्षेत्रों से बाहरी स्रोत व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। हालाँकि, लगभग सभी बैचों में जीपीडीपी सत्र को शामिल किया गया था क्योंकि यह विषय अत्यधिक उपयोगी है और देश भर के पीआरआई ने इसके लिए श्रद्धेय महत्व दिया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में, प्रतिभागियों ने एनआईआरडीपीआर परिसर में स्थित ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) का दौरा किया । प्रतिभागियों को ग्रामीण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आरटीपी में की जा रही विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराया गया । प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक आर्ट ऑफ लिविंग सत्र की भी योजना बनाई गई थी।

हाजीपल्ले ग्राम पंचायत में गाँव के सदस्यों के साथ बातचीत

कार्यक्रम के उद्देश्यों और लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित विधियों का पालन किया गया।

i. व्याख्यान और पारस्परिक सत्र
ii. वीडियो क्लिप और परिचर्चा
iii. एक मॉडल ग्राम पंचायत के लिए क्षेत्र / परिचयात्मक दौरा
iv. समूह अभ्यास और रोल प्ले
v. बेहतर पद्धतियों से परिचय

मॉडल ग्राम पंचायत के लिए क्षेत्र दौरा

विचारों को साझा करने के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों के ज्ञान और क्षमता को साझा करने की दृष्टि से क्षेत्र दौरा किया गया। क्षेत्र दौरे का दूसरा विचार व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना और क्लासरूम शिक्षा को मजबूत करने में प्रतिभागियों की मदद करना था। आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उत्तराखंड के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रदर्शन के लिए चार मॉडल ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। इन पंचायतों की पहचान के लिए एक विचार-विमर्श किया गया था। चयनित ग्राम पंचायतों के नाम निम्नानुसार है:

i. गंगादेवीपल्ली
ii. इब्राहिमपुर
iii. हाजीपल्ले
iv. पेद्दातूपुरा

ग्राम पंचायत में की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी से परिचय कराने के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिभागियों को इन पंचायतों को ले जाया गया। इन पंचायतों के सरपंच और सचिवों ने परिचयात्मक दौरा टीम के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा की और उन्हें उनके संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अब तक किए गए प्रत्येक विकास कार्य के बारे में समझाया। बातचीत के दौरान, पंचायत के सचिव पंचायत द्वारा कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों की योजनाओं, निगरानी और क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया।

चारों पंचायतों की सभी दौरों में, प्रतिभागियों ने ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा उनके पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में अनुभव किए गए चुनौतियों के बारे में सीखा। पंचायत सदस्यों ने उत्साहपूर्वक गाँव की पिछली स्थिति और ग्राम पंचायतों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बहुत खुशी के साथ कहा कि यह सफलता गाँव के सदस्यों के ईमानदार और गम्भीर प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने इसी तरह के जुनून के साथ काम करने और मॉडल ग्राम पंचायत की गरिमा को हासिल करने के लिए परिचयात्मक दौरा टीम के सदस्यों को प्रेरित किया।

डॉ. वाई. भास्कर राव, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संकाय सदस्यों: डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. अंजन कुमार भँज, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. प्रत्यूस्ना पटनायक, सहायक प्रोफेसर और डॉ. विनेश्री जे, सहायक प्रोफेसर और परियोजना कर्मचारी के मार्गदर्शन में पंचायती राज केन्द्र की टीम द्वारा 11 बैचों के लिए प्रशिक्षण का समन्वय किया गया। सदस्य श्री साने मधुसुधन, सलाहकार, डॉ. दामब्रुधर गरदा, परियोजना प्रशिक्षण प्रबंधक, श्री मुनीश जैन, परियोजना प्रशिक्षण प्रबंधक और श्री अबनीश कुमार रे, परियोजना एसोसिएट ने प्रशिक्षण-सह-परिचयात्मक दौरा कार्यक्रमों की श्रृंखला का संयोजन किया।

हाजीपल्ले गाँव के लिए क्षेत्र दौरा

सामुदायिक रेडियो केंद्र, पास्तापुर गांव का क्षेत्र दौरा

पास्तापुर में सामुदायिक रेडियो केंद्र

ग्रामीण गांवों में सामुदायिक रेडियो के कार्यक्षेत्र और कार्य का मूल्यांकन करने के लिए, पास्तापुर में ग्रामीण सामुदायिक रेडियो केंद्र का दौरा करने के लिए एक पायलट अध्ययन किया गया । इसका उद्येश्य आरसीआर के बारे में मूल जानकारी इकट्ठा करना था । रूरल कम्युनिटी रेडियो सेंटर (आरसीआर) एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जिसे मच्चनूर में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसे तीन महिला कर्मचारियों यथा श्रीमती जनरल नरसम्मा, उम्र 35 वर्ष, श्रीमती एल्गोअल नरसम्मा, आयु 32 वर्ष और श्रीमती पुलम्मा, उम्र 35 वर्ष द्वारा चलाया जाता है । ये महिलाएं पिछले 20 सालों से इस संगठन से जुड़े हैं । नरसम्मा की जोड़ी प्रति माह पीएफ सहित लगभग रु. 11,000 और व्यक्तिगत रूप से हर महीने लगभग रु .18,000 कमाते है । यह राशि डीडीएस द्वारा वित्त पोषित है ।

1992 में डीडीएस द्वारा खरीदी गई 15 एकड़ जमीन के एक हिस्से में रेडियो केंद्र को बनाया गया है । रेडियो केंद्र का निर्माण यूनेस्को के प्रायोजित फंडों से किया गया था । यह रेडियो स्टेशन माच्चनूर गाँव में स्थित है जहाँ 1800 से 2000 मतदाता निवास करते हैं और नौ जातियों से संबंधित 200 से 250 परिवार में बसा हुआ है । पहले इस गांव में लोगों को भौगोलिक रूप से जाति के आधार पर अलग कर दिया गया था, लेकिन अब वे अलग-अलग योजनाओं के तहत सरकार द्वारा दी गई जमीन में पड़ोसी परिवारों के साथ मिलाकर रहते हैं ।

यहां पर ट्रांसमीटर 30 किमी के क्षेत्र को कवर करता है । प्रारंभ में, रेडियो केंद्र 1999 से 2008 के बीच संकीर्ण कास्टिंग पर संचालित था, लेकिन भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, प्रसारण शुरू किया गया जब सरकार द्वारा औपचारिक अनुमति दी गई और भारत सरकार द्वारा आवृत्ति आवंटित की गई तब 2018 में आरसीआर ने 2008 से अस्तित्व में होने का अपना दशक मनाया ।

2018 में, भवन को 20,000 रुपये की लागत से वाईटवॉश किया गया जिसके लिए डीडीएस द्वारा वित्त पोषित किया गया । हालांकि स्टूडियो को अच्छी तरह से संरक्षित रखे जाने के बावजूद, दीवारों पर दरारें और टपकन दिखाता है और स्टूडियो की छत पर बिछाई ध्वनिक पैनलों की प्लांट को जाती है । सदस्यों ने 1998-99 से किए गए कार्यक्रमों के सभी कैसेट बनाए रखे हैं, जब वे शुरू में प्रति दिन एक से डेढ़ घंटे के लिए संकीर्ण करना शुरू किए थे । इसके अलावा, वे डीवीडी और हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड किए गए प्रोग्राम को संरक्षित करते हैं । उनके कार्यालय में 1000 से अधिक रिकॉर्डिंग संग्रहित हैं । प्रत्येक डीवीडी में एक निश्चित सप्ताह से संबंधित कार्यक्रम होते हैं । उन्हें पैनल और मिक्सर को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और श्री एम.वी. पाटिल, डीडीएस के बोर्ड सदस्य, श्री सतीश, निदेशक, डीडीएस, हैदराबाद विश्वविद्यालय से डॉ. वासुकी बेलवाडी और 'द हिंदू' से सुश्री सैयदा फरीदा द्वारा रेडियो संपादन करवाते है । इस संगठन में चार मंडलों में बिखरे 52 ग्रामीणों में से 5000 सदस्य संगम सदस्यों के रूप में नामांकित हैं ।

प्रारंभ में, उनकी श्रवणकर्ता 52 गांवों में 30 किमी तक फैली थी । विकसित ट्रांसमीटर खराब होने के कारण इसकी पहुंच केवल 5 किमी तक सीमित थी । डीडीएस उन्हें नए ट्रांसमीटर के लिए फंड नहीं दे सका। क्राउड सोर्सिंग के बाद, एक नया ट्रांसमीटर खरीदा गया और स्थापित किया गया । यह नया ट्रांसमीटर केवल 10 किमी और 30 गांवों तक ही पहुंचता है । संगठन के सदस्यों ने ट्रांसमीटर के उन्नयन के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ।

वर्तमान में, ट्रांसमीटर 30 गांवों को कार्यक्रम प्रसारित करता है, जैसे कि पास्तापुर, अल्गोल, पोट्टुपल्ली, बर्दीपुर, माच्चनूर, कुप्पानगर, चिलपल्ली, रंजूल, बिदेकन्ने, कृत्सशापुर, अलीपुर, भारतनगर, आदि ।

आरसीआर के कार्यक्रम

सभी कर्मचारी दिन में पांच से छह घंटे काम करते हैं, जिसमें सामग्री संग्रह में लगभग तीन-चार घंटे लगते हैं । दो घंटे के दैनिक प्रसारण के लिए, एक समय सारिणी होती है जिसमें कार्यक्रमों की सूची होती है । हर दिन औसतन पाँच से सात कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि 15-20 मिनट के बीच होती है । प्रारंभ में तीस मिनट से एक घंटे की रिकॉर्डिंग की जाती है जिसके बाद

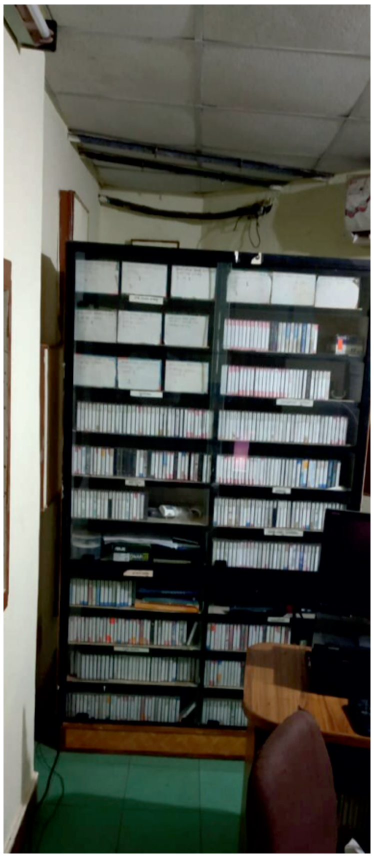

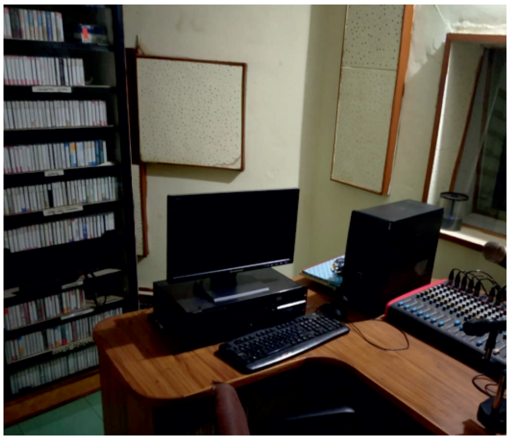

कार्यक्रम को संपादित करने में लगभग दो घंटे लगते हैं ताकि इसे प्रसारित किया जा सके। डीडीएस के पास 52 गाँवों में संगम कार्यकर्ता हैं। महीने के पहले शनिवार को, सभी कार्यक्रमों को प्रसारित करने का निर्णय लेने के लिए सभी पर्यवेक्षकों के साथ एक संगम रेडियो बैठक आयोजित की जाती है। अधिकांश कार्यक्रमों का केंद्रीय विषय 'हमारी गाँव की फसलें' है।

प्रत्येक महीने आयोजित होने वाला एक आम कार्यक्रम गांवों के बीच प्रतिस्पर्धा है। रेडियो कार्यक्रम के बाद, संगम पर्यवेक्षक अंतिम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रति गांव से दो उम्मीदवारों का चयन आरसीआर में आयोजित करते है जिसे किया जाता है। क्विज़ में कृषि से संबंधित विभिन्न विषय होते हैं। विषयों में जुताई, बीज, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे आदि शामिल होते हैं।

प्रत्येक गांव से दो सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई 10 से अधिक गाँव इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। विजयी समूह को डीडीएस द्वारा संचालित सामुदायिक मीडिया ट्रस्ट द्वारा रू. 200 का नकद पुरस्कार वित्त पोषित 200 दिया जाता है। प्रत्येक सप्ताह समूह चर्चा, प्रतियोगिता, साक्षात्कार और स्थानीय देवताओं की कहानियां, स्थानीय गीतों के साथ-साथ भाषाओं पर एक कार्यक्रम या कन्नड़, तेलुगु और लम्बाडी के नए शब्द कवर किए जाते हैं। आरसीआर ने औषधीय पौधों, स्वास्थ्य समस्याओं, मिट्टी की तैयारी, खाद की तैयारी, पशु चिकित्सा विज्ञान, बागवानी के बारे में जानकारी रखने वाले अच्छे गायकों, कहानीकारों और विशेषज्ञों एवं रसोई जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को प्रदान करते की पहचान की है। हर दिन, शाम 7:00 बजे 32-सेकंड का एक जिंगल नियमित रूप से प्रसारण शुरू करता है, जिसके बाद घोषणा और गीत प्रसारित होते है। गाने के साथ कार्यक्रमों में फिर से घोषणा होती है (प्रति दिन लगभग सात गाने प्रसारित होती है)। इस डेढ़ घंटे के कार्यक्रम के बाद एक और आधे घंटे का इंटरएक्टिव प्रोग्राम होता है, जहां लोग गाने का अनुरोध करने या मुद्दों पर बात करने के लिए कॉल करते हैं। इस आधे घंटे के डायल-अप कार्यक्रम को कई लोगों द्वारा प्रसारण की अवधि को बढ़ाने के अनुरोध के बाद जोड़ा गया था। कार्यक्रम के प्रकारों में बिच्चपोलू जनजाति की भागीदारी शामिल है जो भीख मांगने और देवी और देवताओं पर गाने के लिए जाने जाते है। इन गायकों को स्टूडियो में आमंत्रित किया जाता है और एक लाइव प्रदर्शन रिकॉर्ड किया जाता है जिसे संपादित और प्रसारित किया जाता है। आरसीआर नाटक पर कार्यक्रम भी कर रहा है जो शराब, नशे और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर आधारित होता है।

निष्कर्ष

सामुदायिक रेडियो के पास समुदाय को एक मजबूत केन्द्र में बनाये रखने की बहुत संभावना है। रेडियो स्टेशन में जीपीडीपी, सामाजिक लेखापरीक्षा, जल संचयन, सोलार पैनल इंस्टॉलेशन आदि जैसे ग्रामीण विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। कर्मचारियों को उनके कार्यक्रम के भाग के रूप में जमीन पर सरकार को शामिल करने के लिए जुटाया गया था। पीआरआई द्वारा की गई पहल की सराहना की जानी चाहिए और ग्रामीण स्तर पर सरकार क्या कर रहा है का प्रचार किया जाना चाहिए। जिस घोषणापत्र पर लोगों ने पंचायत चुनाव लड़ा और जीता वह चर्चा का मापदंड हो सकता है। उन्हें अपने कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए नवीनतम तकनीक, स्मार्ट फोन के साथ जुड़ने का सुझाव दिया गया। उन्हें विभिन्न समूहों के तहत लोगों को जोड़ने वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सुझाव दिया गया था। इससे उन्हें आसानी से कार्यक्रमों के लिए लोगों को शामिल करने और आमंत्रित करने में सुविधा होगी।

यह सुझाव दिया गया कि कार्यक्रम बनाते समय, 2-3 मिनट व्हाट्सएप वीडियो शूट किया जा सकता। यह वीडियो प्रोग्राम शेड्यूल की घोषणा के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा सकता है। यह संभावित श्रोताओं को आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन के रूप में कार्य करेगा। उन्हें समुदाय की भलाई के लिए आयोजित कार्यक्रमों के साथ महिला सरपंच और एसएचजी सदस्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया। पीआरआई अधिकारी एयर स्पेस का उपयोग एमजीएनईआरईजीए और डीडीयू-जीकेवाई जैसी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए कर सकते हैं ताकि कार्यक्रमों के बारे में समुदाय जागरूक हो सके और उनके हितों के लिए उनका उपयोग कर सके।

सामुदायिक रेडियो अफ्रीकी देशों में जीवन बदल रहा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसका कम उपयोग किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय जमीनी स्तर पर पीआरआई- एसएचजी-आरसीआर अभिसरण के साथ एक नए जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम हो सकते हैं जो न केवल कई मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाएगा बल्कि निचले स्तर पर सरकार में पारदर्शिता के लिए वाचडाग के रूप में कार्य करेगा। उपर्युक्त महिलाएं बहुमुखी, ज्ञानवर्धक और आरसीआर का मुख्य स्रोत हैं। आरडी से संबंधित योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी उपयोगिता फायदेमंद हो सकती है।

इस कार्यक्रम की सफलता दो तरीकों से निर्धारित होती है अर्थात, फोन कॉल और लोगों की अनौपचारिक चर्चा। आम तौर पर, वे रात 8.30 बजे के बाद दर्शकों से फोन कॉल प्राप्त करते हैं, जिसके आधार पर वे विचार करते हैं कि क्या यह कार्यक्रम सफल रहा है या नहीं। वे प्राप्त फोन कॉल के आधार पर कार्यक्रम को संशोधित भी करते हैं। एक और तरीका यह है कि जब वे लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें सराहना मिलती है या लोगों से सलाह लेते हैं।

सफलता की कहानियां

अनसूयम्मा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संगम की सदस्य है जो जीवन अमृत या प्राकृतिक खाद में विशेषज्ञता रखती हैं। वह विभिन्न स्वास्थ्य युक्तियों का एक भंडार है और उसे विभिन्न रीति-रिवाजों / परंपराओं का व्यापक ज्ञान है, जिनका उत्सव समारोह के दौरान पालन किया जाता है। वह नशे और घरेलू हिंसा जैसी विभिन्न समूह चर्चाओं के लिए सामग्री प्रदाता रही हैं। उनकी भाषा सामान्य होने के कारण श्रोताओं द्वारा व्यापक रूप से समझ और सराहना की जाती है। उन्होंने व्यक्त किया कि बहुत से कार्यक्रमों की चर्चाएं बहुत व्यक्तिगत लगती हैं जैसे कि उनके सामने वार्तालाप हो रहा है। महिलाएं अपने पुरुषों या युवाओं से अनुरोध करती हैं कि वे अपने मोबाइल फोन को हर दिन शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच 90.4 एम एच पर छोड़ दें।

नागम्मा पास्तापुर की स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। वह खेतों में निराई करने में माहिर है। वह अपने गांव से परे एक लोकप्रिय गायिका भी हैं और अपनी सुरीली आवाज के लिए जानी जाती हैं। उनको मिली नई प्रसिद्धि ने उन्हें दैनिक जीवन में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों, महिलाओं की जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य के मुद्दों पर गीत, महिलाओं के मुद्दों के साथ-साथ उनके स्वयं के जीवन पर गीत लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। सात साल की उम्र में, वह अपने पति और चार देवरों के बीच रहते हुए घर का सारा काम करती थी। गीत में वर्णित है कि छाले उसके हाथों को कैसे उबालते हैं और फिर फट जाते हैं और दर्द का कारण बनते हैं। वह घर पर आटा पिसाई के दौरान रोती थी और आँसू टपक जाते थे और खो जाते थे। गाने के बोल इतने दिलकश थे कि इंटरव्यू के दौरान कमरे की सभी महिलाएं फूट-फूट कर खूब रोईं।

लक्ष्मम्मा एक अन्य श्रोता और रेडियो के लिए सहयोगकर्ता हैं। उसने कहा कि दिल्ली और हैदराबाद के शहरों में जो रेडियो हम सुनते हैं, वह हमारा रेडियो नहीं है, हम उन रेडियो चैनलों पर प्रसारित कहानियों से संबंधित नहीं हो सकते। "यह आरसीआर हमें हमारे पूर्वजों, हमारी पिछली संस्कृति, हमारे औषधीय पौधों के ज्ञान और स्वदेशी फसल ज्ञान की याद दिलाता है।" वह याद करती है कि कैसे उसका भाई फोन लेकर दौड़ता हुआ आया क्योंकि उसने अपनी बहन की आवाज सुनी क्योंकि वह रेडियो चैनलों के माध्यम से ब्राउज़ कर रहा था। यह गीत जथारा (त्योहार) के दौरान गाया गया था। वह तुरंत प्रसिद्ध बन गई। वह कृषि पर ज्ञान, मिट्टी के प्रकार, बीजों के प्रकार, निश्चित फसल के लिए उपयुक्त भूमि इत्यादि में माहिर हैं। कृषि त्योहारों के बारे में उनकी रुचि बहुत गहरी है।

डॉ. आकाँक्षा शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीडीसी)

सात देशों के पप्रतिनिधियों द्वारा एनआईआरडीपीआर का दौरा

विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डॉ. राजेश कुमार सिन्हा

27 मई, 2019 को चीन, जापान, भारत, कोरिया, मलेशिया, ताइवान और यूनाइटेड किंगडम के 13 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनआईआरडीपीआर का दौरा किया। उनका यह दौरा महाराष्ट्र के पंचगनी में 'परिवर्तन की पहल' पर उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा था। प्रतिनिधियों ने पहले एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) का दौरा किया, जहाँ विभिन्न प्रकार की उपयुक्त ग्रामीण तकनीकों और आय सृजन गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है। बाद में, उन्होंने एनआईआरडीपीआर संकाय, कर्मचारियों और छात्रों के साथ पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की। इस सहभागिता के भाग के रूप में, प्रतिनिधियों ने आंतरिक प्रतिबिंबों के महत्व, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से दूसरों के प्रति आंतरिक आवाज और करुणा को सुनना को साझा किया। बाद में, उनकी प्रतिक्रिया के भाग के रूप में, उन्होंने एनआईआरडीपीआर के काम की सराहना की और आयोजकों को उनकी यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरे का संयोजन डॉ. राजेश कुमार सिन्हा, डॉ. कल्पलता और सीआरटीसीएन की टीम ने किया।

डीडीयू-जीकेवाई के तहत ग्रामीण युवाओं के प्रतिधारण के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला

पहली पंक्ति (बाएं से दाएं) – डॉ. रुबीना नुसरत, सहायक प्रोफेसर, सीईएसडी (चौथे), डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, सीएचआरडी (पांचवे), डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीईएसडी (छठवें) , डॉ. डब्ल्यु.आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (आठवें) और डॉ. संध्या गोपकुमारन, निदेशक, प्रशिक्षण और विकास, डीडीयू-जीकेवाई (चौदहवें)

दूसरी पंक्ति (बाएं से दाएं) - डॉ. सत्य रंजन महाकुल, सहायक प्रोफेसर, सीईएसडी (दूसरे), डॉ. पी. राज कुमार, सहायक प्रोफेसर, सीएफएल (तीसरे) और श्री के. पद्मनाभ राव, अपर परियोजना निदेशक, डीडीयू-जीकेवाई (पांचवे)

डीडीयू-जीकेवाई सेल के प्रशिक्षण प्रभाग, कौशल एवं रोजगार केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने सामाजिक क्षमता एवं विकास केन्द्र के साथ मिलकर 2-3 मई, 2019 के दौरान 'डीडीयू-जीकेवाई' के तहत ग्रामीण युवाओं के प्रतिधारण के लिए 'व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श' पर दो दिवसीय राष्ट्र स्तरीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया।

देश के वंचित ग्रामीण युवाओं के लिए मजदूरी रोजगार के माध्यम से स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए संग्रहण, परामर्श, काउंसलिंग, प्रशिक्षण और स्थान, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कार्यक्रम के चार प्रमुख स्तंभ हैं। परामर्श के लिए एक संरचित, सूचित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता के जवाब में, व्यावसायिक परामर्श और मार्गदर्शन के क्षेत्र में चिकित्सकों, शिक्षाविदों और अन्य विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, ने अपने मुख्य भाषण में जब युवाओं को उचित तरीके से निर्देशित नहीं किया जाता है तो वे निर्मम जहाज की तरह कैसे रह जाते हैं वास्तविक उदाहरणों को बताया। अक्सर, उनकी आकांक्षाएं उनके कौशल सेट से मेल नहीं खाती हैं और उन्हें सही समय पर सुनने, बात करने और निर्देशित करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने विशेषज्ञों से युवाओं को संवारने में व्यावहारिक, उपयोगी और परिवर्तनकारी बदलाव लाने का आग्रह किया, ताकि वे अपने जीवन में सफलतापूर्वक बस सकें और इस प्रकार, राष्ट्र का निर्माण हो सके।

समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र के एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. टी. विजय कुमार ने उल्लेख किया कि युवा दुविधा और भ्रम में होते हैं। इस संबंध में, उन्होंने कहा कि परामर्श और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है इसलिए प्रशिक्षकों / परामर्शदाताओं को कौशल के सेट से लैस किया जाता है ताकि वे इस ग्रामीण युवाओं के कैरियर विकास के लिए उन्हें बनाए रख सकें। एक बार प्रशिक्षक कौशल के उन सेटों से लैस होते हैं, तो वे निश्चित रूप से करियर प्लानिंग और मार्गदर्शन दे सकते हैं।

श्री शंकर दत्त कब्दाल, निदेशक, निगरानी एवं मूल्यांकन ने अनुचित परामर्श के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों और परियोजना को लागू करने वाले भागीदारों के लिए होने वाले विफलता पर प्रकाश डाला।

प्रो. आर.सी. पटेल, डीन, एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा, डॉ. अनिल कुमार, एनसीईआरटी, मैसूर, प्रो. दुलाल मुख्योपाध्याय, डॉ. एल.वी. रेड्डी, पूर्व निदेशक, श्रम मंत्रालय, डॉ. शुभकर गाजुला, हैरिसन असेसमेंट, श्री मधुकर बाबू, कार्यकारी निदेशक, ईजीएमएम, तेलंगाना, श्री राजीव, संचालन प्रमुख, डीडीयूजीकेवाई, राजगिरी कॉलेज, केरल, श्री सत्य नारायण, एसएलसी प्रशिक्षण केंद्र डीडीयू-जीकेवाई के प्रमुख जैसे आमंत्रित वक्ताओं और डॉ. लखन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने युवाओं को कैरियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा, मंच पर नेहरू युवा केंद्र, एसआरएलएम - असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और एनएबीसीओएनएस के प्रतिनिधि शामिल थे जिन्होंने प्रासंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अभिसरण की संभावनाओं को विकसित करने के लिए समाधान प्रस्तुत किया।

मंच ने दो स्तरों के प्रशिक्षण और टूलकिट प्रदान करने के लिए सहमत हुए: व्यावसायिक मार्गदर्शन पर प्रशिक्षकों और पीआईए पदाधिकारियों के लिए छह-दिवसीय प्रशिक्षण और विशेषज्ञों का एक पूल बनाने के लिए परामर्श और कैरियर मार्गदर्शन पर ३०-दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम जो प्रशिक्षण केंद्रों और प्रवास सहायता केंद्रों में युवा ग्रामीणों को समर्थन प्रदान कर सकता है।

डॉ. संध्या गोपकुमारन, निदेशक, प्रशिक्षण एवं विकास, डीडीयू-जीकेवाई और डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र ने कार्यशाला का संयोजन किया।

पशुधन के माध्यम से बेहतर आजीविका पर लाईब्रेरी टॉक

उत्तराखंड के पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए पद्दूपुरा ग्राम पंचायत के पदाधिकारी

डॉ. वाई. रमणा रेड्डी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, आजीविका केन्द्र, एनआईआरडीपीआर ने 7 मई, 2019 को लाइब्रेरी टॉक के भाग के रूप में 'पशुधन के माध्यम से बेहतर आजीविका' पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें मानव संस्कृति के विकास में पालतू पशुओं की भूमिका, पशुधन की आवश्यकता और इसके महत्व, पशुधन और ग्रामीण आय, विशेष रूप से विकासशील देशों में छोटे धारकों के जीवन में, बड़े पशुधन के अवसर, छोटे पशुधन कृषि को बदलने की कार्रवाई, भारत में वर्तमान परिदृश्य आदि शामिल थे।

"जब तक पृथ्वी पर मानव मौजूद है, तब तक भोजन की आवश्यकता रहेगी। भोजन के दो प्राथमिक स्रोत पशु और फसल हैं। कृषि उद्योग के कई प्रभागों में से, पशुपालन सबसे अधिक लाभदायक है और उन्हें लक्षित उपयोगकर्ताओं और स्थानीय बाजार की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना है, "डॉ. रमाना रेड्डी ने कहा।

आजीविका के लिए वैश्विक स्तर पर पशुधन क्यों मायने रखता है, यह बताते हुए उन्होंने कहा कि 1.5 बिलियन लोग छोटे धारक कृषक होते हैं, यह कहते हुए कहा कि भारत में 130 मिलियन स्मॉलहोल्डर के पास चार हेक्टेयर से कम भूमि हैं और एशिया एवं उप-सहारा अफ्रीका में छोटे धारक 80 प्रतिशत या अधिक खाद्य का उत्पादन करते हैं।

उन्होंने कहा कि 43 प्रतिशत या उससे अधिक छोटे धारक महिलाएं हैं और एक अरब से अधिक लोग आजीविका खाद्य सुरक्षा, आय, पोषक तत्व के क्रापिंग और कर्षण, बीमा, और जोखिम प्रबंधन के लिए पशुधन पर निर्भर हैं।

छोटे धारकों के लिए यह पशुधन का 'क्षण' क्यों है, इसे स्पष्ट करते हुए, डॉ. रमणा रेड्डी ने कहा कि चल रहे बदलाव छोटे खाद्य उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और व्यापारियों के लिए अधिक सतत और न्यायसंगत भविष्य के अवसरों को खोलते हैं।

"सही समर्थन के साथ, छोटे पैमाने पर पशुधन उत्पादन प्रणाली सभी के लिए एक सतत और स्वस्थ भविष्य सृजन करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है," उन्होंने कहा।

"दूध, मांस और अंडे की बढ़ती मांग एक वैश्विक घटना है, लेकिन दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में मांग सबसे अधिक है। विकासशील देशों में मांस की खपत में वृद्धि विकसित देशों को पीछे छोड रही है। विकासशील देशों में, दूध का वार्षिक उत्पादन 1.8 प्रतिशत (दक्षिण एशिया में 2 प्रतिशत) बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि विकसित देशों में 0.3 प्रतिशत दूध का उत्पादन होता है। इसी तरह, मांस का उत्पादन विकसित देशों में तीन प्रतिशत से अधिक और विकसित देशों में 0.4 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, "उन्होंने कहा।

अवसरों के बारे में, उन्होंने कहा कि छोटे धारकों के मिश्रित फसल और पशुधन फार्मों पर बड़े पैमाने पर पशुधन और अनाजों का उत्पादन किया जाता है, और विकासशील देशों में दुनिया के अत्यधिक पशुधन खाद्य छोटे मिश्रित खेतों से आता है।

पशु / छोटे धारक खाद्य की विशेषता का वर्णन करते हुए, डॉ. रमणा रेड्डी ने कहा कि 90 प्रतिशत पशु उत्पाद का उत्पादन और खपत उसी देश और क्षेत्र में होते हैं।

"इसके अलावा, अधिकांश छोटे शेयरधारकों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं और 70 प्रतिशत से अधिक पशुधन उत्पादों को अनौपचारिक रूप से बेचा जाता है। इसके अलावा, 500 एम एन छोटे धारक विकासशील-विश्व खाद्य का 80 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कार्यबल का लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा महिलाएँ लेती है और छोटे धारक अभी भी कई देशों में पशुधन उत्पादन पर हावी हैं।

"2018 में, पशुधन ने कृषि जीडीपी का 26 प्रतिशत योगदान दिया, जो कि कुल जीडीपी का 4 प्रतिशत है जिसका मूल्य रु. 8,25,440 करोड़ (यूएस $ 118 बिलियन) है। पशु-स्रोत खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को एक या दूसरे तरीके से पूरा किया जाएगा। हम उस मांग को स्थायी, न्यायसंगत और स्वस्थ तरीकों से पूरा कर सकते हैं जो गरीबी और भूख को भी कम करती है। इसके लिए सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है," उन्होंने कहा।

"स्मॉलहोल्डर निवेश औचित्य बस सबूत के आधार पर और उपभोक्ताओं को पशु स्रोत खाद्य आपूर्ति बढ़ाने और ग्रामीण विकास और आजीविका का समर्थन करने के दोहरे उद्देश्यों पर आधारित है । सबूत हैं: छोटे धारक विकासशील देशों में अधिक मात्रा पशुधन उत्पादन करते हैं, इसलिए उन्हें वृद्धित आपूर्ति रणनीति का हिस्सा बनने की आवश्यकता है; वे प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं, इसलिए अपने दम पर नहीं चले जाते; और वे बड़े वाणिज्यिक प्रणालियों में निवेश करने से नहीं चूकते," उन्होंने कहा ।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण, जलवायु, उपलब्ध फीड्स, स्थानिक बीमारियों, स्थानीय बाजार के संदर्भ, बुनियादी ढांचे और संस्थानों की स्थिति के कारण छोटे धारक उत्पादन को सुधारने के कई प्रयास विफल रहे हैं, उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजार बढ़ रहे हैं लेकिन वे ज्यादातर अनौपचारिक हैं ।

डॉ. रमणा रेड्डी ने आगे बताया कि जूनोसेस का सबसे बड़ा बोझ एक अरब गरीब पशुधन रखने वालों पर पड़ता है ।

"हम छोटे धारकों को प्रतिक्रिया में शामिल कर सकते हैं और गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु आहार की बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं । आने वाले पशुधन संक्रमण और समेकन से खाद्य उत्पादन के साथ-साथ स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण को बेहतर बनाने में लाखों लोगों को मदद मिल सकती है" उन्होंने कहा ।

उन्होंने आगे कहा कि भारत डेयरी आयातक से दुनिया के शीर्ष दूध उत्पादक के रूप में परिवर्तित हो गया है ।

व्याख्यान को पूरा करते हुए, डॉ. रमणा रेड्डी ने कहा कि विकासशील देशों में पशु-स्रोत खाद्य पदार्थों की अभूतपूर्व मांग बढता रहेगा ।

"विकासशील देशों में अधिकांश मांस, दूध और अंडे छोटे धारकों से आता है और उसी देश में उत्पादित और खपत होती है । दुनिया के छोटे धारक पशुधन प्रणालियों में बड़े बदलाव लोगों को लाभान्वित करने वाले तकनीकी और संस्थागत मुद्दों को संबोधित करने के लिए बड़े अवसर प्रस्तुत करते हैं । छोटे धारकों और वाणिज्यिक सिस्टम के साथ काम करने से पशु-स्रोत खाद्य आपूर्ति में सुधार करेगा और ग्रामीण आजीविका को बदलेगा" ।

डॉ. एम. पद्मजा, वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया ।

- सीडीसी पहल

पशुधन के माध्यम से बेहतर आजीविका पर लाईब्रेरी टॉक

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ डॉ. वाई. रमणा रेड्डी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफएल पहली पंक्ति में (पहली पंक्ति में बाएं से पांचवे), डॉ. यू. हेमंत कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएफएल, डीडीयू-जीकेवाई (पहली पंक्ति में बाएं से चौथे) और डॉ. पी. राज कुमार, सहायक प्रोफेसर, सीएफएल (पहली पंक्ति में बाएं से तीसरे)

संस्थान के परिसर में 27 से 31 मई, 2019 के दौरान आजीविका केन्द्र (सीएफएल), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन आई आर डी पी आर), हैदराबाद द्वारा "पशुधन द्वारा बेहतर आजीविका को बढावा देना" पर राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकृत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तीस प्रतिभागियों को नामित किया गया ।

आंध्र प्रदेश से छह प्रतिभागी, हरियाणा से पांच, हिमाचल प्रदेश से चार, कर्नाटक से एक, महाराष्ट्र से तीन, तमिलनाडु से सात और तेलंगाना से चार लोगों ने टीओटी कार्यक्रम में भाग लिया ।

तीस प्रतिभागियों में से 20 प्रतिभागी पशु चिकित्सा क्षेत्र से, तीन कृषि से और सात सामाजिक / विज्ञान क्षेत्र से थे । कैडर-वार, प्रतिभागियों में आठ पशु चिकित्सा सहायक सर्जन / पशु चिकित्सा अधिकारी, दो वरिष्ठ (पशु चिकित्सा) अधिकारी, राज्य पशुपालन विभागों से छह सहायक निदेशक (पशुपालन), तमिलनाडु सहकारी दुग्ध संघ से चार प्रबंधक, राज्य कृषि विभाग से तीन कृषि अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से पांच अधिकारी और एसआईआरडी से एक और राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से एक अधिकारी शामिल हुए ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12 आंतरिक व्याख्यान (आर्ट ऑफ लिविंग पर एक), दो मामला अध्ययन, एक स्थानीय दौरा कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद) शामिल रहे और मुल्कनूर महिला सहकारी डेयरी संघ, मुल्कनूर, वरंगल (शहरी) जिले के लिए दौरा ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को भारत में पशुधन खेती के वर्तमान परिदृश्य और ग्रामीण आजीविका में उनकी भूमिका और कैसे हम पशुस्रोत खाद्य पदार्थों की मांग को ध्यान में रखते हुए पशुधन प्रणालियों के परिवर्तन के माध्यम से छोटे धारक किसानों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और भारत में भविष्य में कैसे बदलाव होने जा रहे हैं के बारे में बताया गया ।

मॉडल सतत खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण

पहली पंक्ति (बाएं से दाएं) – डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआरआई (तीसरे), डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (चौथे), श्री एस आर नल्ली, वाश विशेषज्ञ, यूनिसेफ (पांचवे) और डॉ. आर. रमेश, सहायक प्रोफेसर, सीआरआई (सातवें)

एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ, हैदराबाद ने संयुक्त रूप से 1 और 2 मई, 2019 को "मॉडल सतत खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों" शीर्षक पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षण को एनआईआरडीपीआर परिसर में आयोजित किया गया और इसमें यूनिसेएफ के भागीदारों और परामर्शदाताओं में 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण का उद्घाटन डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद, ने डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआरआई, एनआईआरडीपीआर, श्री सलाथिल नल्ली, वॉश विशेषज्ञ, श्री वेंकटेश अरालीकट्टे, वॉश अधिकारी, यूनिसेफ, डॉ. रमेश रेंगस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर, श्री अरोकियाम काकुमनु, वरिष्ठ राज्य निगरानी एवं मूल्यांकन परामर्शदाता, यूनिसेफ, राष्ट्रीय स्वछता अनुसंधान केन्द्र (एनएससीआर) के परियोजना संयोजक श्री कृष्णा और सुश्री सुधा पोलेनी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में प्रशिक्षण का उद्घाटन किया।

प्रो. शिवराम ने स्वागत भाषण में कहा कि एनएसआरसी प्रोजेक्ट, एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और यूनिसेफ द्वारा समर्थन किया गया है। उन्होंने मॉडल सतत खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों को प्राप्त करने में वर्तमान प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया।

महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने तीन राज्यों में यूनिसेफ समर्थित भागीदारों द्वारा मॉडल स्थायी ओडीएफ ग्राम पंचायत बनाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने लोगों और परियोजनाओं की व्यापक दृश्यता के लिए सभी सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलता की कहानियों के वीडियो प्रलेखन बनाने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा, उन्होंने ग्राम पंचायतों (जीपी) में व्यवसाय मॉडल बनाने की आवश्यकता और अपशिष्ट से संपत्ति तक व्यापार मॉडल जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के सृजन में पंचायतों की भूमिका और ग्राम पंचायतों में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए रीसाइक्लिंग इकाईयों की स्थापना पर जोर दिया।

दो दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य यूनिसेफ समर्थित तीन राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में मॉडल ओडीएफ सतत ग्राम पंचायतों का निर्माण करने में प्रतिभागियों के ज्ञान और कौशल को सुधारना है। विशेष रूप से प्रशिक्षण का उद्देश्य ओडीएफ घोषित गांवों को लर्निंग लैब के रूप में कैसे मॉडल और सतत ओडीएफ जीपी विकसित किया जा सकता है, यह समझने में संभावित परियोजना कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करना है।

प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित रहे है:

- स्थायी मॉडल ओडीएफ जी पी के संकेतकों पर चर्चा और सहमति देना
- स्थायी मॉडल ओडीएफ जी पी बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा करना और अंतिम रूप देना
- संभावित ओडीएफ जीपी के विस्तृत मूल्यांकन के लिए अनुसंधान उपकरणों और विधियों को अंतिम रूप देना
- रेट्रोफिटिंग, सामुदायिक निगरानी प्रणाली और प्रमुख वॉश दिशानिर्देशों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना
- स्थायी मॉडल ओडीएफ जी पी के निर्माण के लिए तीन महीने की कार्य योजना विकसित (और सहमति देना) करना

अगले सत्र में बल क्षेत्र विश्लेषण के माध्यम से 'सतत ग्राम पंचायत ओडीएफ स्थिति' की अड़चनों पर चर्चा की गई। श्री वेंकटेश, वॉश अधिकारी, यूनिसेफ ने एक प्रस्तुति दी और इस संबंध में चर्चा का निरीक्षण किया। मॉडल ओडीएफएस जीपी और इस संबंध में ढांचा तैयार करने के लिए संभावित सक्षम कारकों और अक्षम कारकों को

साथी-वार समूहों द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए थे। प्रतिभागियों द्वारा ओडीएफ जीपी मॉडल के लिए विभिन्न पहचान नामों को प्रस्तावित किया गया । मॉडल स्थायी ओडीएफ जीपी को 'स्वच्छ स्वस्थ सुंदर ग्राम पंचायत' के रूप में बुलाने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा, श्री अरोकियम द्वारा और श्री कृष्णा द्वारा सुगम तरीके से 'संभावित मॉडल ओडीएफ जीपी स्तर' के मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण टूल्स' पर विचार-मंथन और चर्चा की गई । साझेदारों को घर पर स्वच्छता की स्थिति, गाँव के स्वच्छता सर्वेक्षण, स्कूल और एडब्ल्युसी का वॉश मूल्यांकन पर मौजूदा सर्वेक्षण उपकरणों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद चर्चा की गई । यह निर्णय लिया गया कि अंतिम सर्वेक्षण उपकरण को ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे।

हर दिन का प्रशिक्षण पहले दिन में आयोजित विभिन्न सत्रों के पुनर्कथन और महत्वपूर्ण सीख के साथ शुरू किया गया, जिसे प्रतिभागियों द्वारा भी साझा किया गया। इसके अलावा, डॉ. राम मोहन ने 'घरेलू शौचालयों की रेट्रोफिटिंग' पर एक सत्र चलाया, जिससे भारत में स्वच्छता कार्यक्रम की स्थिति, शौचालय के प्रकार, शौचालय प्रौद्योगिकी, रेट्रोफिटिंग उपायों आदि पर प्रतिभागियों को एक संक्षिप्त विचार प्राप्त हुआ । उन्होंने शौचालय प्रौद्योगिकी और रेट्रोफिटिंग के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षुओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं और संदेहों को स्पष्ट किया।

अगले सत्र में सुश्री सुधा पोलेनी, परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय स्वछता संसाधन केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा हितधारकों का 'विश्लेषण और जीपी ओडीएफ स्टेटस' को निरंतर बनाये रखने में उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी' पर चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया । सुश्री सुधा ने अपने सत्र में मुख्य अवधारणाओं की व्याख्या की, जैसे – हितधारक कौन है, हितधारकों के प्रकार, हितधारक विश्लेषण का महत्व, हितधारक प्राथमिकता और प्रबंधन उपकरण। अवधारणाओं को समझाने के बाद, अभ्यास के भाग के रूप में, प्रतिभागियों को उनके परियोजना स्थलों में मॉडल को स्थायी ओडीएफ जीपी बनाने के लिए उनके प्रभाव / शक्ति एवं रुचि / प्रभाव का विश्लेषण करने और हितधारकों की पहचान / सूची बनाने के लिए समूहों में विभाजित किया गया। प्रशिक्षकों द्वारा समूह कार्य को सुविधाजनक बनाया गया था और अंत में, प्रतिभागियों ने अपने समूह के कार्य निष्कर्षों को सभी के साथ प्रस्तुत किया । सुश्री सुधा द्वारा हितधारक प्रबंधन उपकरण का उपयोग करके विश्लेषण के आधार पर हितधारकों का प्रबंधन कैसे करें, यह समझाकर सत्र का समापन किया गया।

इसके बाद स्थायी मॉडल ओडीएफ जीपी बनाने के लिए गतिविधियों की पहचान और प्राथमिकता' पर विचार मंथन और समेकन सत्र आयोजित किया गया जिसका संचालन श्री कृष्णा, परियोजना संयोजन, राष्ट्रीय स्वछता संसाधन केन्द्र, एनआईआरडीपीआर और श्री दिनेश, कर्नाटक राज्य वॉश परामर्शक, यूनिसेफ द्वारा किया गया। प्रमुख गतिविधियों (क्षमता निर्माण, जमीनी स्तर के संस्थानों का सुदृढीकरण एसबीसीसी / आईईसी, सामाजिक मानदंडों, नेटवर्किंग और लिंकेज, आदि) पर सत्र, श्री अरोक्यम द्वारा सत्र संचालित किया गया।

इन सत्रों में मॉडल सतत ओडीएफ जीपी बनाने के प्रमुख बिंदु हैं:

1. योजना और संबंधित चरण
2. निचले स्तर के संस्थानों का सुदृढीकरण - (निगरानी समितियाँ, वीडब्ल्युएससी, जीपी, जाति-आधारित समूह, युवा समितियाँ, एसएचजी समूह / संघ, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, धार्मिक नेता, आदि)।
3. एसबीसीसी / आईईसी हस्तक्षेप
4. प्रमुख हितधारकों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) का क्षमता निर्माण
5. अभिसरण और गठबंधन निर्माण
6. निगरानी और रिपोर्टिंग
7. निर्माण और रेट्रोफिटिंग
8. निधि संग्रहण

अंतिम पहले वाले सत्र में, क्षमता निर्माण / आईईसी गतिविधियां जो कि स्थायी ओडीएफ जीपी बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, प्रत्येक सहभागी द्वारा अपने परियोजना के लिए प्रस्तुत की गई । श्री दिनेश और श्री सुबास ने जीपी ओडीएफ स्थिति बनाने और बनाए रखने के लिए संसाधनों की मैपिंग पर विचार प्रस्तुत किया । विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध निधियों को शौचालय निर्माण, रेट्रोफिटिंग, आईईसी/क्षमता निर्माण, इंस्टीट्यूशन (स्कूल/एडब्ल्युसी/ स्वास्थ्य केंद्र), एसएलडब्ल्युएम, एमएचएम, आदि जैसे विभिन्न घटकों के लिए शिनाख्त और उपयोग किया जा सकता है।

अंतिम सत्र में, छह महीने के मॉडल स्थायी ओडीएफ जीपी बनाने हेतु ढाँचा कार्य को कार्य योजना में परिवर्तित करने के लिए सभी साझेदारों से एक टेम्पलेट बांटा गया । सभी भागीदारों ने मॉडल ओडीएफ जीपी बनाने के लिए टेम्पलेट का उपयोग करके अपने परियोजना प्रस्ताव के आधार पर कार्य योजना तैयार की और प्रस्तुत किया। नीचे दिए गए टेम्पलेट पर सत्र में चर्चा की गई:

कार्य योजना तैयार करने के बाद, स्रोत व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण बाद मूल्यांकन किया गया । प्रशिक्षण का समापन डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआरआई, एनआईआरडीपीआर द्वारा स्रोत व्यक्तियों, यूनिसेफ सलाहकारों और प्रतिभागियों की उपस्थिति में प्रेरणादायक व्याख्यान से हुआ। सुश्री निहारिका, प्रशिक्षु, ने डॉ. पी. शिवराम, यूनिसेफ के कर्मचारियों, एनआईआरडीपीआर टीम, आयोजकों और अन्य हितधारकों के लिए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

कार्य का स्वरूप	लक्षित समूह	कार्यक्रमों की संख्या	प्रारंभ दिनांक	समाप्ति तारीख	स्रोत वित्त पोषण	विभिन्न एजेन्सियों से

ग्रामीण उद्यमिता, नवाचार और वित्तीय समावेशन पर टीओटी कार्यक्रम

प्रिमेरो अपेरल पार्क (कुदुम्बश्री यूनिट), पुनालूर, केरल के दौरे पर एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण कर्मचारी और टीओटी कार्यक्रम के प्रतिभागी

वित्तीय समावेशन की उपलब्धि से समग्र विकास और देश का संपूर्ण विकास होता है । आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्यमशीलता को सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है । सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए सूक्ष्म वित्त ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन उद्यमियों के लिए ऑक्सीजन है । यह युवाओं के कौशल और उद्यमिता विकास का आह्वान करता है, जिन्हें न केवल आवश्यक उद्यमशीलता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, बल्कि नवोन्मेषी उद्यमशीलता गतिविधियों को भी अपनी आजीविका के विकल्प के रूप में देखना है । इस बैकलॉग के विरूद्ध, एनआईआरडीपीआर के सीएफआईई ने एसआईआरडी-केरल के सहयोग में किला-सीएचआरडी, कोट्टारक्करा में 13-15 मई 2019 के दौरान 'ग्रामीण उद्यमिता, नवाचार एवं वित्तीय समावेशन' पर तीन दिवसीय टीओटी कार्यक्रम का आयोजन किया ।

कार्यक्रम का उद्घाटन और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, डॉ. के. रामकृष्ण, सलाहकार, सीएफआईई, एनआईआरडीपीआर ने कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया और इसके उद्देश्यों को बताया। श्री वी. सुदेशन, संकाय (उप विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति पर), किला -सीएचआरडी ने इस अवसर पर बात की और प्रतिभागियों को कक्षा एवं क्षेत्र खंडों से प्राप्त शिक्षण का अच्छा उपयोग करने के लिए कहा ।

कार्यक्रम की विषय वस्तु

- भारत में वित्तीय समावेशन: अतीत, वर्तमान और भविष्य
- वित्तीय समावेशन में एमएफआई और उनकी भूमिका
- वित्तीय साक्षरता: एसएचजी के कामकाज में सुधार और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गुंजाइश
- ग्रामीण उद्यमिता: एमएफआई की भूमिका
- एमएसएमई: ग्रामीण विकास के लिए स्थिरता और नवाचार; वित्तीय समावेशन पर मामला अध्ययन - एमयूडीआरए ऋण
- सतत आजीविका कार्यक्रम - मुर्गी पालन, डेयरी और अन्य संबद्ध गतिविधियाँ
- ग्रामीण विकास के लिए मितव्ययी नवाचार
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
- कृषि वित्त में उभरते क्षेत्र; कृषि बीमा और जोखिम प्रबंधन

कार्यक्रम

कार्यक्रम में पच्चीस प्रशिक्षुओं (एसआईआरडी, ईटीसी के संकाय और इंटर्न के छात्रों के साथ-साथ कुडुंबश्री के सलाहकारों) ने भाग लिया ।

संसाधन व्यक्ति / संकाय

सीएफआईई के आंतरिक संकाय सदस्य और चयनित अतिथि संकाय (एसआईआरडी और अन्य विभाग) जो डोमेन क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञ-सह व्यवसायी हैं, कार्यक्रम में योगदान दिए ।

प्रशिक्षण क्रियाविधि

टीओटी कार्यक्रम की अवधि और प्रतिभागियों की अपेक्षाओं के पीपीटी, मामला अध्ययन, वीडियो क्लिप और चर्चा, व्यक्तिगत और समूह की गतिविधियों, क्षेत्र / परिचयात्मक दौरे और पुनर्कथन सत्रों की मदद से व्याख्यान और इंटरेक्टिव सत्र जैसे विविध पद्धतियों का उपयोग किया गया ।

व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने और कक्षा में किए गए शिक्षण को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए कार्यक्रम के दूसरे दिन (14-05-2019) को निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए दौरे आयोजित किए गए ।

(ए) प्रिमेरो अपैरल पार्क, पुनलूर:

प्रतिभागियों को मेसर्स प्रिमेरो अपैरल पार्क, पुनलूर ले जाया गया । उनकी गतिविधियों और शासी निकायों के बारे में बाते हुए सुश्री शमी गणेशन, अपैरल इकाई के सचिव ने बताया कि पुनलूर नगरपालिका की 50 बेरोजगार महिलाओं के एक समूह का चयन किया गया और उनकी इकाई स्थापित करने के लिए किटको, निफ्ट और जुब्बा रामकृष्ण पिल्लई फाउंडेशन, त्रिशूर में प्रशिक्षण दिया गया । जबकि सदस्यों ने प्रति व्यक्ति 2,500 रुपये (बैंक डिपॉजिट) की दर से 1,25,000 रूपये इकट्टा किए । जिला कुदुम्बश्री मिशन (डीकेएम) से 50 लाख, अनुदान राशि मिली जिसे उन्होंने अपैरल तैयारी से संबंधित 48 मशीनों को खरीदने के लिए उपयोग किया । पुनलूर नगरपालिका कॉम्प्लेक्स के भीतर स्थापित इकाई को स्थानीय सरकारी निकायों से किराया-मुक्त आवास, मुफ्त बिजली और पानी के रूप में प्रचार समर्थन प्राप्त हुआ । इकाई श्रम अनुबंध के आधार पर काम करती है, अर्थात्, पास के कपड़ा स्टोर से कच्चा माल खरीदना, तैयार उत्पादों को वितरित करने और प्रक्रिया में श्रम शुल्क प्राप्त करने के लिए अब, उन्होंने विभिन्न वस्तुओं जैसे कि फ्रॉक, स्कूल की वर्दी, नाईट वेयर, चूड़ीदार, कपड़े की थैलियाँ, फर्श मैट आदि की सिलाई करके अपनी गतिविधियों में विविधता लाई है । व्यापार इकाई सभी महत्वपूर्ण रजिस्टरों का रखरखाव करता है और निकट भविष्य में व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की स्पष्ट दृष्टि से स्व-प्रेरित महिलाएँ सक्रिय रूप से रोटेशन आधार पर काम करती है ।

(बी) निर्मलयम न्यूट्रिमिक्स यूनिट:

ऐकरक्कोनम वार्ड, पुनालुर से नौ बेरोजगार महिलाओं का एक समूह ने एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस व्यवसाय उद्यम को शुरू करने में शामिल हुए । स्व-प्रेरित महिलाओं ने इस इकाई (मार्च, 2008) को स्थापित करने से पहले ईडीपी, लेखाकरण और बही खाता, और करावलूर न्यूट्रिमिक्स यूनिट में एक सप्ताह के कौशल प्रशिक्षण जैसे विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त किए । टीम खुले बाजार से गेहूं (एफसीआई द्वारा आपूर्ति), मूंगफली, सोयाबीन और चीनी जैसे कच्चे माल की खरीद करती है, उन्हें संसाधित करती है और आंगनवाड़ियों को अमृतम पाउडर (होम-होम राशन) के रूप में आपूर्ति करती है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्यान्नों का अनूठा मिश्रण टेक-होम पूरक आहार है जिसे कुपोषण के खिलाफ लडने में मदद करने के लिए केरल सरकार की सहायता से बच्चों की पोषण स्थिति (६ महीने से ३ वर्ष) में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई । यह टेक होम राशन स्ट्रैटेजी (टीएचआरएस) के तहत संचालित होता है जो आंगनवाड़ियों के माध्यम से एक फीडिंग कार्यक्रम है । इकाई के निवेश स्रोत है – रु. 2,50,000 (बैंक ऋण) + रु. 3,00,000 (कुडुम्बश्री से प्रौद्योगिकी निधि) + और रु. 25,000 जिला कुदुम्बश्री मिशन (डीकेएम) से और गतिविधि से लाभ है रु. 600 प्रति व्यक्ति प्रति दिन । इकाई आठ पंचायतों और पुनलूर नगर पालिका के 250 आंगनवाड़ियों (रु. 70 प्रति किग्रा + 5 प्रतिशत जीएसटी) के लिए न्यूट्रिमिक्स पाउडर की आपूर्ति करता है । डीकेएम और पुनलूर नगरपालिका, उद्यम के सुचारू संचालन के लिए अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं ।

डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफआईई के मार्गदर्शन में, डॉ. के. रामकृष्ण, सलाहकार और सुश्री ए. सरिशा, प्रबंधक (प्रशिक्षण) द्वारा कार्यक्रम का संयोजन किया गया ।

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

संपादक : डॉ. के पापम्मा
सहायक संपादक: कृष्णा राज
के.एस. विक्टर पॉल

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका